04 - खनिज संसाधन बदल रहे हैं विश्व राजनीति

05 - आधुनिक कृषि की चुनौतियां, किसान हित और जीएम बीजों का भविष्य

A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 04 फरवरी, 2026

06 - भारतीय पत्रकार संघ का 555 वां सम्मेलन खरगोन में, देशभर के...

07 - 'रोगी से न करें भेदभाव, कुष्ठ रोग के बारे में हो जागरूक'

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 154, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

यूजीसी विवाद : ऐतिहासिक फैसला करने का समय आ गया है

संतोष कुमार पाठक

सही मायने में देखा जाए तो यूजीसी नियमों पर मचे घमासान या यूं कहें कि ताजा विवाद ने दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत को एक बड़ा मौका दे दिया अगर इस बार चूक गए तो फिर आने वाले कई दशकों तक यह विवाद देश और समाज की शांति को और हम सबको भंग करता रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर फिलहाल रोक तो लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ अगड़ी जातियों के लोग सड़कों पर थे और अब इसके समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। विवाद चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, यह तनाव लाता है और समाज की शांति को भंग करता है। इसलिए विवाद को टालने की बजाय हमेशा स्थाई समाधान को तलाशने के लिए काम करना चाहिए।

सही मायने में देखा जाए तो यूजीसी नियमों पर मचे घमासान या यूं कहें कि ताजा विवाद ने दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है और हम अगर इस बार चूक गए तो फिर आने वाले कई दशकों तक यह विवाद देश और समाज की शांति को भंग करता रहेगा।

सामान्य भाषा में कहें तो हमारे देश के संविधान ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हो। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत तो यही रहा है कि 'सौ दोषी भले छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।' यह सिद्धांत हमें स्पष्ट तौर पर बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर पूरे समाज के भरोसे को बरकरार रखने के लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी हालत में वर्ष, महीने, दिन और घंटे तो छोड़िए, एक सेकंड के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

इस कसौटी पर रखकर जब यूजीसी के नियमों को तौला जाता है तो यह साफ-साफ नज़र आता है कि यूजीसी ने अपने नियम के जरिए भारत के लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत को ही कुचलने की तैयारी कर ली थी। कई लोग यह तर्क भी देते हुए नजर आए कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। कुछ लोगों ने कई अन्य कानूनों के दुरुपयोग का उदाहरण दिया तो कुछ लोगों ने हज़ार वर्षों के शोषण का जिक्र करते हुए इसे सही ठहराया।

हालांकि भारत के लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह मामला सिर्फ अगड़ा बनाम पिछड़ा भर का नहीं रह गया है और इसे रहना भी नहीं चाहिए। आज़ादी के 75 वर्षों बाद अब यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हमारी व्यवस्था कानून का पालन करने वाले निर्दोष लोगों के साथ न्याय कर पा रही है। यह आपको अजीब लगेगा लेकिन सही मायनों में अब हमें इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए कि आखिर बिना किसी सजा के लोगों को दिन, महीने, साल ही नहीं दशकों तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून, दहेज, महिला उत्पीड़न सहित उन तमाम कानूनों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है जो पुलिस को बिना किसी जांच के गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं।

एक लोकतांत्रिक देश में बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग हज़ारों वर्षों के शोषण की याद दिलाते हैं,उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके स्तर को उठाने और भेदभाव खत्म करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और देश का अगड़ा वर्ग भी पिछले कई दशकों से इसे स्वीकार कर चुका है। लेकिन किसी को भी इतना अधिकार तो नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी और जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को बिना मतलब कानूनी विवाद में उलझा दें अथवा जेल भिजवा दें।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि, लोग ना जाने क्यों इस तथ्य को भी भुला देते हैं कि हज़ार साल पहले की शासन व्यवस्था चाहे जैसी भी रही हो लेकिन इस देश में पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र है, संसद है, न्यायपालिका है और मीडिया भी है। अगर हज़ार साल पहले ऐसा कुछ हुआ भी होगा जिसका दावा आमतौर पर किया जाता है तो क्या उसका बदला अब एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश में लेने की इजाज़त दी जा सकती है। यह तो 'आंख के बदले आंख' लेने जैसा नियम लागू हो जाएगा।

वाद-विवाद में तथ्यों और आंकड़ों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लेकिन दुर्भाग्य से आज के माहौल में कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे सब अपना-अपना दायरा पहले ही तय कर चुके हैं और कोई भी इससे आगे जाना ही नहीं चाहता।

शोषण कौन कर रहा है और शोषण किसका हो रहा है, यह तो किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के परसेप्शन के आधार पर तय नहीं हो सकता, इसकी गवाही तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ें ही दे सकते हैं और जैसे ही आप आंकड़ों को सामने रखते हैं तो सारी कहानी ही पलटी हुई नजर आती है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि बार-बार आबादी के बहाने इस विवाद को सुलगाने की कोशिश करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो फिर संविधान निर्माताओं की भावना का सम्मान करते हुए ऐसे लोगों को जिनकी आबादी कम है, उन्हें तो कई तरह के विशेषाधिकार देने पड़ेंगे।

इसलिए, इस विवाद को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करना अब बहुत जरूरी हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बार-बार आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का दावा कर रही है तो क्या एक विकसित भारत में भी हमारा देश अतीत की गठरी लेकर ही प्रवेश करेगा? इस सवाल का जवाब अब तो ढूंढ ही लेना चाहिए।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव का ऐलान

आदिवासियों के प्लाट की रजिस्ट्री कराएगी राज्य सरकार

सरदार सरोवर डैम के विस्थापितों के लिए बड़ा फैसला, धनवाही और बरही सिंचाई परियोजना भी मंजूर

सिंहस्थ 2028 के लिए बाबा महाकाल की नगरी में बसेगी भव्य टेंट सिटी

भोपाल (नप्र)। सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित 25,602 आदिवासी परिवारों को दिए गए आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री अब सरकार कराएगी। इसके लिए इन परिवारों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र और चार जिलों के विस्थापित शामिल हैं।

विस्थापन के समय इन परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे दिए गए थे पर रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी। रजिस्ट्री को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। वहीं कैबिनेट ने धनवाही और बरही सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कई विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुजरात प्रवास के दौरान कच्छ के 'रण उत्सव' की भव्यता और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में भी इसी तर्ज पर एक विशाल और विश्वस्तरीय टेंट सिटी विकसित की जाएगी। पीएम मोदी के मॉडल को अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू किया जाएगा।

कर्मचारियों का विलय होगा- इसके अलावा सरकार ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास में विलय करने की स्वीकृति दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पहली बार भोपाल में 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह केवल फूलों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि फूलों के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक उत्सव था।

पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण- बैठक में बताया गया कि महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया गया है। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। यह भी बताया गया कि प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का भुगतान 2 माह के अंदर किया। मप्र देश का पहला राज्य है, जिसने भावांतर योजना का पूर्णतः लागू किया।

18 फरवरी को आएगा एमपी का बजट

सीएम मोहन यादव बोले- एमपी में कम हो रही बेरोजगारी, केंद्रीय बजट की खूबियां बताईं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर डेढ़ प्रतिशत तक रह गई है और तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। ये बात मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। वे राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी केंद्रीय बजट पर बात करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट एक आत्मा से तालमेल करते हुए चल रहा है। बजट में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने का काम किया गया है। केंद्रीय बजट सिर्फ कागजीकरण नहीं है बल्कि भविष्य को लेकर तैयार किया गया प्लान है।

पाकिस्तान को अमेरिका से कर्ज की जरूरत- बजट के पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें हुई हैं, उससे बजट के परिणाम का आकलन किया जा सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका से कर्ज की जरूरत होती है, इसलिए वह अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता है, लेकिन हमारे देश की स्थिति उलट है।

रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि केंद्रीय बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। इसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, हर जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केंद्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों की दवाऐं भी सस्ती होंगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा है कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है, इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। बजट में देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, इसका आने वाले दिनों में प्रदेश और देश को तरक्की में बड़ा योगदान होगा।

दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने बजट के बाद कहा था कि केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करेगा। जिन क्षेत्रों में दुनिया के केवल दो-तीन देशों का दबदबा है, उन रणनीतिक उत्पादों के निर्माण पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में पहली बार अलग मालगाड़ी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। खण्डेलवाल ने कहा है यह बजट डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है।

शहरों के विकास पर खर्च होंगे 5000 करोड़ रुपए

इसके साथ ही पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास पर पांच साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोहन यादव ने कहा कि छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। हर जिले में महिला छात्रावास बनाएंगे। जिला अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को वस्त्र उद्योग में लाभ मिलेगा। पीएम मित्र पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा।

मोहन यादव ने कहा कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह प्रदेश और देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान देगा। इससे कई काम आसान हो जाएंगे।

इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह बजट मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास, समावेश प्रगति और दीर्घकालिक विकासोन्मुख और भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हमारा बजट दुनिया को नई दिशा दे रहा है। अपने पड़ोसियों का हाल देख लीजिए। पैसे के लिए पाकिस्तान को कितना जलील होना पड़ रहा है।

निजता के अधिकार के साथ खेल नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सऐप और मेटा को फटकारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि टेक कंपनियां डेटा साझा करने के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ खेल नहीं सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप एलएलसी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ी और आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं और कहा कि अदालत उन्हें भारतीयों के निजी डेटा का शोषण करने की अनुमति नहीं देगी।

अदालत मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप एलएलसी द्वारा दायर उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने व्हाट्सऐप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा था।

देश के अधिकारों के साथ नहीं खेल सकते

चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इन मामलों की सुनवाई की। मेटा और व्हाट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है। अपीलों को स्वीकार करने पर सहमति जताते हुए भी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। आप इस देश के अधिकारों के साथ नहीं खेल सकते।

पीएम मोदी डरे हुए, उन पर बहुत दबाव है

● राहुल बोले- ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं ● अमेरिका- भारत ट्रेड डील पर विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। उन पर बहुत दबाव है। सरकार घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी पर भयंकर प्रेशर है। ये साइड शो है। ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। संसद के बजट सत्र में विपक्ष अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि डील में अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट पर 0 फीसदी टैरिफ पर हामी भरी गई है। जो देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी ने मंगलवार को भी लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल पर भी बोलना चाहा, लेकिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल, अमेरिका ने भारत पर लगाए 50 टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। ट्रम्प ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस ने अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- वॉशिंगटन में मोगैम्बो खुश है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने आखिरकार हार मान ली है।

● **लोकसभा में राहुल के बयान पर दूसरे दिन भी हंगामा-** लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा- मुझे बोलने दिया जाए। उनके यह कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। राहुल ने कहा- %मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। मैं बस बता रहा हूं की चाइना-इंडिया के बीच में क्या हुआ। पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक शहीद हुए। हंगामा के दौरान पीठासीन की तरफ पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रशांत परोले, एस वेंटकटरमण, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी ईडन, गुरजीत औजला और डीन कोरियोकोज शामिल हैं।

शरद की सुबह

रास्ते जो भी चमक-
दार नज़र आते हैं
सब तेरी ओढ़नी के
तार नज़र आते हैं

कोई पागल ही मोहब्बत
से नवाज़ेगा मुझे
आप तो ख़ैर समझदार
नज़र आते हैं

मैं कहाँ जाऊँ करूँ किस से
शिकायत उस की
हर तरफ़ उस के तरफ़-
दार नज़र आते हैं

ज़ख़्म भरने लगे हैं
पिछली मुलाक़ातों के
फिर मुलाक़ात के
आसार नज़र आते हैं

एक ही बार नज़र पड़ती है
उन पर 'ताबिश'
और फिर वो ही लगातार नज़र आते हैं

- जुबैर अली ताबिश

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 04 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने की 385 ई-वाहनों की रिकॉर्ड डिलीवरी

भोपाल/हैदराबाद। देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने इस दौरान 663.60 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह रही कि ओलेक्ट्रा ने एक ही तिमाही में रिकॉर्ड 385 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की, जो साल-दर-साल 37त्न की बढ़ोतरी दर्शाती है।

कंपनी का एबिटा बढ़कर 97.10 करोड़ रहा, जबकि कर पश्चात लाभ 46.68 करोड़ दर्ज किया गया। अब तक ओलेक्ट्रा कुल 3,639 इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर कर चुकी है और इसके पास 9,439 वाहनों की मजबूत ऑर्डर बुक है।

प्रबंध निदेशक महेश बाबू ने कहा कि ब्लेड बैटरी तकनीक के प्रमाणन और नई बसों के आगामी उत्पादन से कंपनी की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन में ओलेक्ट्रा अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी।

केंद्र के समान 25 लाख रू. ग्रेच्युटी देने की मांग

भोपाल। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु लिए गए निर्णयानुसार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% होने के फलस्वरुप केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% वृद्धि कर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है । पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेशदत्त जोशी व प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने अपने पत्र मे कहा कि मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को भी 1 जनवरी 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किए हैं एवं इसके अंतर्गत प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 50त्न महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है । विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा भी 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 सभी तरह की उपादान की राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख की गई है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियो को 1 जनवरी 24 से सेवानिवृत्ति पर 20 लाख के स्थान पर 25 लाख ग्रेच्युटी भुगतान करने किया जाए ।

पटियाला की नाभा जेल से बाहर आए बिक्रम सिंह मजीठिया

- सात महीने बाद मिली रिहाई, सैकड़ों की तादाद में जुटे समर्थक

पटियाला (एजेंसी)। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया मंगलवार को यहा नई नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ज़मानत दी थी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को मजीठिया को उनके अमृतसर वाले घर से आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के ड्रग्स के पैसे की मनी

लॉन्ड्रिंग शामिल थी। बिक्रम सिंह मजीठिया के समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल के बाहर जमा हुए और समर्थन में नारे लगाए। समर्थकों ने उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। अकाली नेता की पत्नी, गनीव कौर मजीठिया भी मौजूद थीं और उन्होंने भगवान और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। गनीव कौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह सच्चाई की जीत है। सरकार भूल गई थी कि ऊपर भगवान भी है। जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मजीठिया के समर्थकों को मिठाई के डिब्बे लाते हुए देखा गया। अमृतसर में उनके घर के बाहर,मजीठिया के समर्थक जमा हुए, मिठाइयां बांटी।

डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे मजबूत, 90.20 पर आया

- यह 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त, 2025 में सबसे कमजोर एशियाई करेंसी हो गया था

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 90.20 के स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इससे पहले 2025 में रुपया करीब 5 फीसदी तक टूटकर एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था। जनवरी 2026 में ही इसमें 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार निकासी ने रुपए पर दबाव बना रखा था। हालांकि,मंगलवार को रुपए ने वापसी करते हुए 91.49 के मुकाबले 130 पैसे की मजबूती दर्ज की है।

ट्रेडडील के ऐलान के बाद आई तेजी

रुपए में आई इस तेजी के पीछे भारत और अमेरिका के बीच हुआ 'गिव एंड टेक' समझौता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बदले अमेरिका व वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसके अलावा, भारत ने अगले कुछ वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर (करीब 45 लाख करोड़ रुपए) की एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इस ऐलान ने उस अनिश्चितता को खत्म कर दिया है जो पिछले साल अगस्त में अमेरिका के टैरिफ के बाद से बनी हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपए में यह तेजी अभी और जारी रह सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, निर्यात बढ़ने की उम्मीद से रुपए की मांग में और इजाफा होगा। शॉर्ट टर्म में रुपया 89.50 से 89.00 के स्तर पर जा सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी का कहना है कि टैरिफ में कटौती से रुपए के लिए मजबूती के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक किस स्तर पर हस्तक्षेप करता है। करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं।

अगस्ता वेस्टलैंड सेना के लिए फिर हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी

- भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रिश्वत देने का आरोप था

नई दिल्ली (एजेंसी)। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट मिलने के पांच साल बाद फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। यह वही कंपनी है, जिसका नाम बहुचर्चित हेलीकॉप्टर कांड से

जुड़ा था। इसने करीब एक दशक तक भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अडाणी ग्रुप के अनुसार इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। लियोनार्डो कभी फिनमैकेनिका के नाम से जानी जाती थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का घोटाला है।

बंगाल में कोयला तस्करी मामले में ईडी का ऐक्शन

- कोलकाता व दुर्गापुर समेत 9 ठिकानों पर मारा छापा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह यानी 3 फरवरी 2026 को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान सहित कुल नौ स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य कोयला तस्करी से अर्जित काले धन के लेन-देन के तरीकों का पता लगाना है। जांच एजेंसी को शक है कि तस्करी की इस बड़ी रकम को हवाला के जरिए ठिकाने लगाया गया है। ईडी इसी वित्तीय ट्रेल को ट्रैक करने के लिए डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों को खंगाल रही है। कोलकाता के साथ-साथ दुर्गापुर में भी ईडी ने मंगलवार सुबह करीब 6 बजे से सेपको टाउनशिप में बालू कारोबारी के आवास पर छापेमारी की जा रही है। सिटी सेंटर क्षेत्र के आंबेडकर सरणी स्थित एक संदिग्ध घर की तलाशी ली जा रही है। पांडवेश्वर और कांकसा में एनएच-19 (नेशनल हाईवे) के पास स्थित ठिकानों पर भी अधिकारियों ने छापामारी की है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये कारोबारी अजय और दामोदर नदी से बालू निकालने के कार्य से जुड़े हैं।

जाति की गणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए

एससी बोला- सत्यापन जरूरी, केंद्र और अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2027 की जनगणना में जाति गणना सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इसे किसी भरोसेमंद तरीके से या सबूत के आधार पर करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने आकाश गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल बिना जांच वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि वे जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे सत्यापित सामग्री के आधार पर किया जाना जरूरी है। यह डेटा कई सालों तक योजनाओं, आरक्षण और नीतियों का आधार बनेगा, इसलिए यह सिर्फ आत्म-घोषणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। जनगणना एक विशेष और तकनीकी प्रक्रिया है। यह तय करना जनगणना अधिकारियों और विशेषज्ञों का काम है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता की चिंताओं को प्रतिनिधित्व के रूप में रखा जा सकता है।

- **वकील बोलीं-जनगणना का सीधा असर आरक्षण पर पड़ेगा-** सीनियर वकील मुक्ता गुप्ता ने कहा कि हम प्रमाण पत्र की पूरी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ सामग्री होनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि सब कुछ आत्म-घोषणा पर आधारित है। बिना सत्यापन की आत्म-घोषणा बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बता सकता है। जनगणना 2027 पर करीब 13,500 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है और इसका सीधा असर देश की सभी कल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण नीतियों पर पड़ेगा।

94 लाख गरीबों के लिए नीतिश सरकार ने खोला खजाना

- बिहार में पेश हुआ 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख का बजट

पटना (एजेंसी)। बिहार में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपए का है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया। इस बार बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 3.17 लाख करोड़ के मुकाबले करीब 30 हजार करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को सात निश्चय-3 के जरिए से विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। सरकार का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर है, जिसके तहत प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार के भविष्य का रोडमैप साझा करते हुए पांच मूल तत्वों की घोषणा की। उन्होंने कहा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के स्तंभों पर चलकर ही बिहार प्रगति करेगा।

सिंधु जल समझौते की सुनवाई में शामिल नहीं होगा भारत

- कहा- यह कोर्ट ही अवैध है, इसके आदेशों को नहीं मानते

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि वह इस अदालत की वैधता को नहीं मानता और इसकी किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि जब सिंधु जल संधि को ही भारत ने स्थगित कर रखा है, तो उस संधि के तहत बनी किसी संस्था को जवाब देने की बाध्यता नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फरवरी 2-3 को नीदरलैंड्स के पीस पैलेस में सुनवाई तय की है। साथ ही भारत के बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़े 'पोंडेज लॉगबुक' दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। भारत ने इन आदेशों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 24 जनवरी 2026 के आदेश में कहा कि अगर भारत मौजूद नहीं रहता, तो पाकिस्तान अकेले ही सुनवाई में दलीलें देगा। इसके बाद 29 जनवरी को कोर्ट ने भारत से बगलिहार और किशनगंगा प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशनल रिकॉर्ड मांगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो वह मान सकता है कि ये कागजात जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं और इससे उनके खिलाफ फैसला जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि भारत ने संधि को रोकने का जो फैसला लिया है, उससे

कोर्ट के मामले सुनने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत का कहना है कि मौजूदा विवाद तकनीकी है और इसे न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। सिंधु नदी के पानी को लेकर जब भी कोई तकनीकी विवाद होता है, तो उसे सुलझाने के लिए न्यूट्रल (निष्पक्ष) एक्सपर्ट की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान सिंधु जल संधि में पहले से तय है। न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई अदालत नहीं होता। वह एक स्वतंत्र और तटस्थ तकनीकी विशेषज्ञ होता है, जो पानी से जुड़े तकनीकी सवालों पर राय देता है। भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया था। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47 जमीन पाकिस्तान, 39 जमीन भारत, 8 जमीन चीन और 6 फीसदी जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच झगड़ा शुरू हो गया था।

- भारत लेकर आ रहा है ब्रह्मोस का भी 'बाप'

हाइपरसोनिक ताकत से थर-थर कांपेगा पाकिस्तान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की मिसाइल क्षमता अब एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे पाकिस्तान अब तक कांप रहा है, अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज

एक नई मिसाइल भारत विकसित कर रहा है। इसकी जानकारी खुद डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के चेयरमैन डॉ समीर वी कामत ने दी है। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि नई लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत-रूस के संयुक्त उद्यम वाली मिसाइल प्रणालियों से कहीं अधिक सक्षम है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में डॉ कामत ने बताया कि हमने दो विकासात्मक परीक्षण पूरे कर लिए हैं और जल्द ही तीसरा परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद हम इसे उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद इन मिसाइलों को सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। हम इस प्रणाली पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और यह हमारी सेनाओं के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जब उनसे डीआरडीओ की मिसाइल से तुलना करने के बारे में पूछा गया,तो उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं अधिक क्षमताओं वाली होगी।

अमेरिका ट्रेड डील में भारत के हितों से समझौता नहीं

- पीयूष गोयल बोले-ट्रम्प को धन्यवाद, उन्होंने मोदी से मित्रता का सम्मान किया; राहुल की सोच निगेटिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को अमेरिका से ट्रेड डील पर मीडिया को ब्रीफ किया। गोयल ने कहा कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। दोनों देश इस डील पर जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। यह एक ऐसी डील है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की। जो लोग अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर ऐसे सेक्टर जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है और जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। सभी इससे उत्साहित हैं। गोयल ने कहा कि ये डील करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद, उन्होंने पीएम मोदी की मित्रता का सम्मान किया। पीयूष गोयल ने कहा- इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा।

हेलीकॉप्टर में खराबी

बाल-बाल बचीं पंकजा मुंडे

- महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रही थीं लातूर

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री और भाजपा नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है। उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर में खराबी का पता चलने से एक बड़ा हादसा टल गया है। पंकजा मुंडे मंगलवार को जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए लातूर जा रही थीं। जानकारी सामने आई कि संभाजीनगर से लातूर के लिए पंकजा हेलीकॉप्टर से जाने वाली थीं। छत्रपति संभाजीनगर से लातूर के लिए उड़ान भरने से पहले ही पायलट को यह खराबी दिखी। इसके बाद उन्हें जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए संभाजीनगर से लातूर तक की अपनी तय हेलीकॉप्टर यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। इस अचानक खराबी के कारण पंकजा मुंडे की लातूर में होने वाली सभाओं का समय भी बदल दिया गया है। हालांकि, इस हेलीकॉप्टर के साथ असल में क्या हुआ है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जिला परिषद चुनाव के लिए पंकजा मुंडे लगातार प्रचार कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर के बजाजनगर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने बजाजनगर जिला परिषद ग्रुप नंबर 50 और 51, जबकि ग्रुप

नंबर 49, दौलताबाद जिला परिषद ग्रुप के मतदाता से पब्लिक मीटिंग में बातचीत की। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में उनका निधन हो गया। अन्य 4 लोग भी विमान दुर्घटना में मारे गए थे।

मध्यप्रदेश में यूजीसी को लेकर आदेश जारी

लोकपाल के आदेश सिर्फ सलाह नहीं, कॉलेजों को करना होगा पालन

झूठी शिकायत पर शिकायकर्ता पर भी हो सकती है कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2023 को अब सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं होगी।

लोकपाल के आदेश मानना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा और यदि कोई शिकायत झूठी या बेबुनियाद पाई गई तो उस पर शिकायत करने वाले छात्र के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के दायरे में आने वाले संस्थानों पर लागू होगा। इसका मकसद छात्रों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।

झूठी शिकायत पर भी कार्रवाई संभव- सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो लोकपाल शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे यूजीसी के छात्र शिकायत निवारण नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लोकपाल अनिवार्य- यूजीसी के नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति जरूरी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अधिकतर संस्थानों में लोकपाल तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अब स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि छात्र अपनी शिकायत को लेकर भटकें नहीं।

लोकपाल छात्रों के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण होगा। वह उन्हीं मामलों को सुनेगा, जिनमें छात्र पहले छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) की प्रक्रिया पूरी कर चुका हो।

छात्र को पता हो, शिकायत कहां और कैसे करें- सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में अहम जानकारी साफ-साफ दिखाए। जिसमें छात्र शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के नाम, पद और संपर्क विवरण, लोकपाल का नाम, पता, ई-मेल और कार्यकाल, शिकायत और अपील दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी छात्र को यह न कहना पड़े कि उसे जानकारी ही नहीं थी।

प्रॉस्पेक्टस 60 दिन पहले करना होगा जारी- एडमिशन से पहले छात्रों को पूरी और सही जानकारी मिले, इसके लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा।

प्रॉस्पेक्टस में कोर्स की जानकारी, सीटों की संख्या, फीस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, रिफंड नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, लाइब्रेरी, रैगिंग-रोधी व्यवस्था और फैकल्टी का विवरण देना अनिवार्य होगा।

अगर प्रॉस्पेक्टस की हार्ड कॉपी बेची जाती है तो उसकी कीमत सिर्फ छपाई खर्च तक सीमित रहेगी। इससे मुनाफा कमाना गलत माना जाएगा।

गलत जानकारी दी तो छात्र कर सकेगा शिकायत- यदि प्रॉस्पेक्टस में गलत या भ्रामक जानकारी दी गई और छात्र को नुकसान हुआ, तो छात्र इसकी शिकायत SGRC या लोकपाल से कर सकता है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसी शिकायतें पूरी तरह स्वीकार्य होंगी।

हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) बनाना अनिवार्य होगा। इसमें एक प्रोफेसर अध्यक्ष, चार वरिष्ठ शिक्षक, एक छात्र प्रतिनिधि और कम से कम एक महिला और एक एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग का सदस्य को शामिल रहेंगे। एसजीआरसी को शिकायत मिलने के 15 वर्किंग डे के अंदर अपना फैसला या सिफारिश संस्था प्रमुख को भेजनी होगी और उसकी प्रति छात्र को देना जरूरी होगा।

एसजीआरसी से संतुष्ट नहीं तो लोकपाल के पास अपील

अगर छात्र एसजीआरसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 15 दिन के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है। लोकपाल 30 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा करने का प्रयास करेगा। खास बात यह है कि लोकपाल के आदेश सिर्फ सुझाव नहीं होंगे, बल्कि उनका पालन करना कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा।

किन मामलों में छात्र कर सकता है शिकायत

- प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी
- तय फीस से ज्यादा राशि मांगना
- फीस रिफंड में देरी
- स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता न मिलना
- परीक्षा या रिजल्ट में अनावश्यक देरी
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन
- एससी,एसटी,ओबीसी महिला या दिव्यांग छात्रों से भेदभाव
- शिक्षा की गुणवत्ता या सुविधाओं में कमी
- छात्र उत्पीड़न या मानसिक प्रताड़ना

ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना होगा

हर संस्थान को एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना होगा, जहां छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उसे SGRC को भेजना होगा और सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

यूजीसी के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना का मशाल जुलूस

8 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालेंगे कार्यकर्ता, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

भोपाल (नप्र)। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के खिलाफ क्षत्रिय करणी सेना भोपाल में मशाल जुलूस निकालेगी। यह जुलूस 8 फरवरी की शाम 6 बजे भारत माता चौराहा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष और भोपाल जिला अध्यक्ष आशु सिंह ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश महिला अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान करेंगी। जुलूस में हजारों करणी सैनिकों के शामिल होने की संभावना है।

सवर्ण समाज के लोग भी शामिल होंगे

इसके साथ ही सवर्ण समाज के नागरिक भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। आशु सिंह के अनुसार यूजीसी से जुड़े हालिया निर्णयों को लेकर समाज में असंतोष है। इसी के विरोध में यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी।

किसान निर्धारित समय पर करायें पंजीयन : खाद्य मंत्री राजपूत

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक

भोपाल (नप्र)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है।

पंजीयन की नि :शुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, मेक इन इंडिया को देगी नई गति : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। भारत-अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील अभिनन्दनीय है। यह ट्रेड डील, मेक इन इंडिया को नई गति देगी। इससे देश को प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह डील भारत के सशक्त नेतृत्व और विकास में साझा विश्वास को दर्शाता है।

19 साल बाद 6 ग्रहों के विशेष योग में महाशिवरात्रि

भक्तों के लिए यह विशेष फलदायी, महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू

उज्जैन (नप्र)। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के संधिकाल में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। ऐसे में त्रिकोण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसे विशेष फलदायी माना जाता है। पूरे साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ज्योतिष पंडित अमर डिब्बावाला के अनुसार, इस बार ग्रहों का दुर्लभ पुनरावृत्ति योग बन रहा है। इससे पहले ऐसा संयोग 2007 में बना था। करीब 19 साल बाद एक बार फिर इन्हीं ग्रहों की स्थिति में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा।

महाकाल मंदिर में तैयारियां शुरू

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 6 फरवरी से शिवरात्रि पर्व के तहत मंदिर के मुख्य शिखर की धुलाई, मंदिर परिसर की रंग-रोगन, कोटितीर्थ कुंड की सफाई और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया है। मंदिर प्रांगण में स्थित 40 मंदिरों की पुताई का काम अंतिम चरण में है। इस संबंध में मंगलवार शाम कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और समिति सदस्यों के साथ बैठक कर दर्शन व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे।

चार प्रहर की पूजा से मिलती है सिद्धि और सफलता

शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा प्रदोष काल से लेकर निशिथ काल (मध्य रात्रि) और ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस दौरान श्रद्धालु अपने संकल्प के अनुसार सपरिवार या साधक विशेष पूजा-अनुष्ठान कर सकते हैं।

भोपाल चैंबर चुनाव में गोविंद गोयल जीते

अध्यक्ष पद के दावेदार तेजकुल पाल सिंह को 191 वोट से हराया

भोपाल (नप्र)। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के चुनाव में गोविंद गोयल जीत गए हैं। कुल 1999 वोटों में से गोयल को 1085 और तेलकुल पाल सिंह पाली को 894 वोट मिले हैं। इस तरह गोयल 193 वोट से जीत गए हैं। 13 वोट रिजेक्ट हुए हैं। कुल 40 राउंड की गिनती होने के बाद गोयल को विजयी घोषित कर दिया गया है।

सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होना थी, लेकिन तीन घंटे बाद ही थाने से पेटियां निकल पाई। उम्मीदवारों की मौजूदगी में पेटियां श्यामला हिल्स थाने में जमा करवाई गई थी। चूंकि, देर शाम तक वोटिंग चली और फिर वोटिंग प्रतिशत से जीत-हार का अंतर निकालने के चलते उम्मीदवार सुबह समय पर मानस भवन नहीं पहुंच सके। इस कारण काउंटिंग में देरी हुई।काउंटिंग के समय गोविंद गोयल का परिवार उनकी स्व. धर्म पत्नी की तस्वीर लेकर पहुंचा था।

दोपहर 12 बजे तक मतों के बंडल बनाए जाने लगे। इसके बाद गिनती शुरू हुई। गोविंद गोयल और तेजकुलपाल सिंह पाली में से कोई एक चैंबर का नया अध्यक्ष बनना था। चैंबर भोपाल के व्यापारियों की बड़ी संस्था है, इसलिए सभी एसोसिएशनों का भी इसे समर्थन मिला है। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल के मैदान में उतरने से चुनाव और भी दिलचस्प हो गया था। रविवार को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 2 हजार व्यापारियों ने वोट डाले। इनमें टेंडर और पोस्टल बैलेट भी शामिल हैं।

अध्यक्ष पद के लिए गोयल और पाली के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोनों ही इस पद के दावेदार हैं। करीब 170 सदस्यों की टीम ने मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई। पर्यवेक्षक डॉ. पीसी कोठारी और सीएम वैभव जैन ने बताया कि पॉलीटेक्निक कॉलेज चौराहा स्थित मानस भवन में मतगणना की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्यामला हिल्स थाने से मतपेटियां लाने के बाद वोटों की गिनती की जा रही है।

मंत्री चेतन कश्यप ने किया भोपाल प्रेस क्लब के कैलेंडर का विमोचन

भोपाल। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने सोमवार को भोपाल प्रेस क्लब के टेबल कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल, सतीश सक्सेना, संजय सक्सेना, हाकम सिंह गुर्जर, देवकीनंदन पाण्डेय, दीनानाथ पटेल मौजूद रहे।

म्युनिसिपल बॉन्ड- केंद्र की नीति पर महापौर का दावा

जिस म्युनिसिपल बॉन्ड को मेयर इंदौर की देन बता रहे हैं, वह 2017 में आ चुका

इंदौर (नप्र)। भागीरथपुरा जल कांड से उठे सवालों के बीच महापौर ने जमीनी सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए एक और बड़ा दावा उछाल दिया। इस बार निशाने पर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में लॉन्च की गई म्युनिसिपल बॉन्ड योजना, जिसका श्रेय महापौर ने इंदौर नगर निगम को दे डाला।

महापौर ने एक दिन पहले मीडिया के सामने दावा किया कि केंद्रीय बजट में नगरीय निकायों के लिए घोषित बॉन्ड प्रावधान इंदौर निगम द्वारा जलूद सोलर प्लांट के लिए लाए गए ग्रीन बॉन्ड से प्रेरित है। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार भी जताया।

महापौर का दावा पूरी तरह बोगस- म्युनिसिपल बॉन्ड की मूल योजना केंद्र सरकार ने 2017 में ही लॉन्च कर दी थी। उस वक्त अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए तय की गई थी। जबकि ताजा बजट में कोई नई योजना नहीं लाई गई, बल्कि सिर्फ बड़े नगर निगमों के लिए सीमा बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की गई है।

इंदौर भी बॉन्ड पहली बार नहीं लाया- महापौर का यह दावा भी गलत है कि इंदौर निगम ने जलूद सोलर प्लांट के लिए पहली बार बॉन्ड जारी कर इतिहास रचा। इससे पहले 2018 में इंदौर निगम ने अमृत योजना के लिए 140 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इतना ही नहीं इस पर केंद्र सरकार ने 18.2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। महापौर 2023 में जलूद सोलर प्लांट के लिए 244 करोड़ का बॉन्ड लाया गया। इस पर केंद्र ने 20 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया था।

स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी- वित्तीय जानकारों के मुताबिक, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी म्युनिसिपल बॉन्ड संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। ऐसे में यह दावा कि केंद्र ने इंदौर के प्रयोग को देखकर नीति बनाई, यह भी गलत ही है।

2017 से देश के दर्जनों नगर निगम जारी कर चुके बॉन्ड- 2017 के बाद देश के दर्जनों नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुके हैं। 2019 में ही केंद्र सरकार ने विभिन्न निगमों को 181.33 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांटा था। इंदौर के अलावा भोपाल नगर निगम भी 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड ला चुका है।

'चंबल' में नोटरी से शादी..फिर दुल्हन की किडनैपिंग का खेल

गर्लफ्रेंड और सहेलियों से कराई शादी, रुपए के बदले कुंवारों से गैंग करती थी सौदा

ग्वालियर(नप्र)। डकैतों के लिए कुख्यात चंबल अब लुटेरी दुल्हनों के लिए चर्चित हो रहा है। पिछले कुछ समय से यहां नोटरी पर शादियां कराई जा रही हैं। इसके बाद गैंग के सदस्य दुल्हन का अपहरण कर लेते हैं। कुछ मामलों में दुल्हन खुद भी फरार हो जाती है।

21 जनवरी को ऐसा ही एक मामला सामने आया। ग्वालियर का एक कारोबारी परिवार बेटे की शादी कर दुल्हन को घर ले जा रहा था। तभी दाल बाजार में कार रुकवाकर कुछ युवकों ने हंगामा किया और कुछ ही देर में दुल्हन का अपहरण कर फरार हो गए।

मामले की जांच शुरू हुई तो पूरे रैकेट की परतें खुलती चली गईं। ग्वालियर में सात सदस्यीय गैंग इस तरह कुंवारों को जाल में फंसाकर रुपये और गहने ऐंठ रहा था। इस गैंग ने एक ठेकेदार के मानसिक दिव्यांग बेटे की शादी के लिए सुंदर दुल्हन का दो लाख रुपए में इंतजाम कराया था।

नोटरी पर शादी के बाद जब परिवार दुल्हन को लेकर घर जा रहा था, तभी बाइक और एक्टिवा सवार युवक दुल्हन के रिश्तेदार बनकर आए और उसे जबरन ले भागे। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।

पुलिस ने खुलासा किया कि सात सदस्यीय गैंग ने इसी तरह की वारदातें ग्वालियर से पहले श्योपुर के विजयपुर और पन्ना जिले में भी की हैं। दुल्हन के लिए गैंग अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियों का इस्तेमाल करता था।

23 जनवरी को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस सीन रीक्रिएशन के लिए आरोपियों को घटना स्थल ले गई थी।

बीच बाजार वारदात की, खुल गया गैंग का राज- नोटरी पर शादी के बाद ठेकेदार महेंद्र अपने बेटे और नई बहू को कार से घर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान दाल बाजार में एक बाइक और एक्टिवा पर सवार होकर आए पांच युवकों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। सभी मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने जमकर हंगामा किया। कार के कांच तोड़ दिए।

जबरन कार का गेट खुलवा कर युवती का अपहरण कर ले गए। उन्होंने दुल्हन बनी पूनम से वादा किया था कि उसे एक दिन भी दूल्हे के साथ नहीं गुजारने देंगे। लेकिन, गैंग से चूक यह हो गई कि उन्होंने पहली बार बीच बाजार ऐसी वारदात की। पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कड़ियां जोड़ते हुए इस गैंग तक पहुंच गई। मामले में 2 युवतियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कॉन्ट्रेक्टर ने मानसिक दिव्यांग बेटे के लिए खरीदी दुल्हन

ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड निवासी महेंद्र पाराशर कॉन्ट्रेक्टर हैं। उनके बेटे अस्मित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। बेटे अस्मित की शादी के लिए उन्होंने कई परिचित से कह रखा था। बेटे के शादी के लिए उनके परिचित राकेश शर्मा ने जौरा निवासी बंटी धाकड़ से मुरैना के पचोखरा में मुलाकात कराई थी।

इस दौरान बंटी ने कहा कि उसका एक रिश्तेदार है। वह दो लाख रुपए में शादी की डील करा देगा। सारी बात हुई और दो लाख रुपए देकर शादी की बात तय हो गई। 21 जनवरी को बंटी धाकड़ ने हजीरा स्थित गार्डन में दो लाख रुपए ले लिए। रुपए लेने के बाद बंटी धाकड़ 22 जनवरी को दुल्हन पूनम गौड़ निवासी हजीरा को शादी कराने के लिए लेकर आया था। इससे पहले इदरगंज में शादी की नोटरी भी कराई गई।

संपादकीय

ग्रेमी अवॉर्ड: चीन का भड़कना बेमानी

तिब्बत के वयोवृद्ध धर्म गुरू, आध्यात्मिक नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा को इस साल संगीत का प्रतिष्ठित ग्रेमी अवॉर्ड देने पर चीन का भड़कना बेमानी है और शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। यह संभवतः पहला मौका है, जब किसी धर्मगुरू को ग्रैमी अवॉर्ड से नवाजा गया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार उनके एल्बम 'मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा' के लिए दिया गया है, जो उनकी धार्मिक शिक्षाओं को संगीत से जोड़ता है। यह अवॉर्ड उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑडियोबुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में मिला है। 'दलाई लामा के इस एल्बम का संगीत प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और उनके पुत्रों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने तैयार और प्रस्तुत किया है। इस अल्बम में रूफस वेनराइट, मैगी रोजर्स और आंद्रा डे जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने भी योगदान दिया है। यह प्रोजेक्ट ग्रैमी विजेता कबीर सहगल द्वारा तैयार किया गया है। दलाई लामा द्वारा 90 वर्ष की उम्र में अवॉर्ड जीतना भी अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। दलाई लामा का यह अल्बम उनकी शिक्षाओं को प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों तक शांति और करुणा के संदेश को पहुंचाना है। अपनी धार्मिक आस्था और शांति दूत के रूप में दुनिया में मशहूर दलाई लामा को बौद्ध धर्म के उस नेता के रूप में जाना जाता है, जिसने 21वीं सदी में नए नजरिये और सोच से एक नया समाज रचा है। अवॉर्ड मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया में दलाई लामा ने कहा कि मैं इस पुरस्कार को 'हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी की मान्यता' के रूप में देखता हूं।' दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी तिब्बती मातृभूमि के लिए अधिक स्वायत्तता की अथक मुहिम चलाने वाले दलाई लामा की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है, जिसे बीजिंग अपना 'अभिन्न अंग' कहता है। दलाई लामा जब 23 साल के थे, तो 1959 में चीनी सेना से अपनी जान बचाने के लिए तिब्बती राजधानी ल्हासा से भागकर भारत आ गए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि यह उनके आध्यात्मिक नेता का 14वां पुनर्जन्म है। दलाई लामा को ग्रैमी अवॉर्ड देने पर चीन ने अमेरिका को खरी-खोटी सुनाते हुए इसे 'राजनीतिक हेरफेर' बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका सांस्कृतिक मंचों का चीन के खिलाफ 'हथियार' के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस पुरस्कार के जरिये अमेरिका ने दलाई लामा की 'अलगाववादी छवि' को सफेद करने की कोशिश की है। चीन ने कहा कि दलाई लामा कोई साधारण धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे धर्म का चोला पहन कर चीन विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं। इस अवॉर्ड का मकसद दलाई लामा के राजनीतिक एजेंडे को अंतरराष्ट्रीय मंच देना है। हालांकि चीन यह भूल गया कि ग्रैमी अवॉर्ड कोई अमेरिकी सरकार नहीं देती, 'द रिकॉर्डिंग अकादमी' देती है। उसके अपने मापदंड हैं। ग्रैमी पुरस्कारों की शुरूआत 1959 में हुई थी और इन्हें संगीत के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे, इस साल अमेरिका के लास एंजेल्स में हुई अवॉर्ड समारोह में कई ग्रैमी विजेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए खुलकर आलोचना की तो ट्रंप ने भी जवाब में कलाकारों को खरी खोटी सुनाई। दरसअल दलाई लामा को पुरस्कृत करने के लिए चीन द्वारा अमेरिका की आलोचना तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे को जायज ठहराने की कोशिश है। चीन के इस विस्तारवादी रवैये को भारत भी कभी स्वीकार नहीं करेगा।

खनिज संसाधन बदल रहे हैं विश्व राजनीति

नजरिया

डॉ. ललित कुमार
लेखक इनवर्टिस विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।

दुनिया के हर कोने में इस वक्त एक नई वैश्विक राजनीतिक चेतना और वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची है। यानी हर ग्लोबल राजनेता अपने देश को आगे निकालने की कतार में खड़ा है। सत्ता में आते है उनके मनसूबे साफ नजर आने लगते हैं कि वह चाहते क्या है? पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर एक अलग ही प्रकार का राजनीतिक नेरेटिव देखने को मिल रहा है। जिसका सबसे ताजा उदाहरण है अमेरिका, जो यूरोप की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखता है। क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसी के इशारे पर चलती है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखा, जो दुनिया को हथियार सप्लाई करके खुद को सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा। तब से अब तक उसने सभी की जरूरत को पूरा किया और अपने सुपर पावर होने का रुतबा बरकरार रखा।

इसलिए यूरोपीय संघ, अरब और नाटो जैसे देश अमेरिका के हाथों की कठपुतली हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि वह जब चाहे किसी भी देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। ईरान का ताज़ा उदाहरण सबसे सामने है। वर्तमान दौर में खनिज संसाधनों पर कब्जा करना अब अमेरिका की नियति बनती जा रही है। इससे यह संकेत तो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि वह लगातार टैरिफ लगाकर दुनिया को परेशानी में डालने का काम कर रहा है। जिसके ज़रिए वह दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है।

ट्रंप प्रशासन साउथ अमेरिका (वेनेजुएला), यूरोप (रूस-यूक्रेन), एशिया (चीन-ताइवान), मध्य पूर्व (ईरान इजरायल), और अफ्रीका में भी मोर्चा खोले हुए हैं। अब सवाल है कि अमेरिका एक साथ जो इतना रायता फैलाएं हुए है। उसे समेट पाना बड़ा मुश्किल भी हो सकता है। यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश इस वक़्त अमेरिका की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल हुए हैं। अमेरिका अपनी सीमाओं से सटे अन्य देशों की सरज़मीं पर रूस, चीन और उत्तर कोरिया को रोकना चाहता है। इस दौर में अमेरिका फर्स्ट एक्शन की नई व्यवस्था बनाकर खुद को फिर से महान बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

अमेरिका जिन महाद्वीपों के खनिज संसाधनों पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। उसमें वेनेजुएला उसके एजेंडे में सबसे पहले है, जिसके राष्ट्रपति को वह गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल चुका है। यानी अमेरिका साफ तौर पर तेल पर कब्जा करना चाहता है, जिससे रूस और चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिका रूस पर प्रतिबंध जारी करके यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका फ्रांस जर्मनी को भी धमकी दे चुका है कि वह अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करें नहीं तो वहां से अपनी सेना हटा लेगा। पोलैंड और बाल्टिक देशों में रूस को घेरने के लिए नाटो में अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा चुका है। अमेरिका ताइवान शहर में

एयरबेस बनाकर उसे हथियार सप्लाई करके चीन को दक्षिण सागर में रोकना चाहता है। उत्तर कोरिया में अमेरिका वहां के मिसाइल टेस्ट पर प्रतिबंध लगा चुका है। यानी किम जोंग के खिलाफ भी वह मोर्चा खुले चुका हैं। फिलिपींस, वियतनाम और जापान में भी अपनी साझेदारी बढ़ाएं हुए है।

अमेरिका भारत को अपने व्यापार में 500 फ़ीसदी टैरिफ का डर दिखाए हुए है। मध्य-पूर्व में इजराइल का समर्थन देकर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ चुका है। इजरायल-गाजा युद्ध में इजरायल की मदद करके वह हमास को रोकना चाहता है, उधर सीरिया-इराक़ में आईएसआईएस के नाम पर अपनी सेना तैनात करके रूस की सभी योजनाओं पर पानी फेर चुका है। उधर सऊदी अरब में अमेरिका तेल डील मजबूत करके यमन पर भी युद्ध का दबाव बनाए हुए हैं।

'द सेक्रेटेरिएट' वेबसाइट पर वर्ष 2024 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ्स) के सबसे बड़े प्रसंस्करणकर्ता चीन ने इन तत्वों की निकासी और पृथक्करण (एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन) से जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर भारी प्रतिबंध लगा दिए है। इस प्रतिबंध ने यह भी उजागर किया कि किस प्रकार बहुत कम देश इन महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक व्यापार पर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे अधिक देश अपने हरित उद्योगों (ग्रीन इंडस्ट्रीज़) को ऊर्जा देने के लिए इन सामग्रियों की मांग बढ़ा रहे हैं, उसका असर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की किस दिशा में जा सकता है। निकेल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज, तथा नियोडिमियम, स्कैंडियम और यट्रियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और आधुनिक तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में किया जाता है। ये तत्व कार्बन उत्सर्जन कमी की दिशा में भी बहुत सहायक माने जाते हैं, जिसमें लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में सबसे ज्यादा होता है।

डीडब्लू वेबसाइट की एक ओर रिपोर्ट बताती है चीन बड़े पैमाने पर म्यांमार के काचिन राज्य में दुर्लभ खनिजों का खूब दोहन कर रहा है। चीन कंपनिया पहाड़ की चोटी पर छेद करते हैं और फिर अमोनियम नाइट्रेट जैसे रसायनों को उसके जरिए जमीन में डालते हैं ताकि नीचे से दुर्लभ खनिजों को निकाला जा सके। यह रसायन नीचे की तरफ बहते हुए दुर्लभ खनिजों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। जो बाद में जाकर बड़े-बड़े तालाबों में जमा हो जाता है। चीन अपने घरेलू खनिजों को कम करके, पड़ोसी देश, म्यांमार के खनिज भंडारों पर अपनी नज़र गडाए बैठा हैं, जहां वह लगभग दो दशकों से खनिजों का दोहन कर रहा है।

ग्लोबल विटनेस की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने म्यांमार से भारी दुर्लभ खनिजों का आयात 2021 में 19,500 टन से बढ़ाकर 2023 में 41,700 टन कर दिया है। अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर, जूली क्लिंगर ने बताया कि 'दुर्लभ खनिज' शब्द का मतलब उन 17 तत्वों से है, जो रासायनिक रूप से समान हैं। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, 'इन तत्वों की खासियत यह है कि इनमें अद्भुत चुंबकीय (मैग्नेटिक), विद्युत चालक (कंडक्टिव) और कुछ में तो तापीय गुण (थर्मल) भी होते हैं।' इन्हें अक्सर 'उद्योग जगत का मसाला' भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होने पर भी यह औद्योगिक प्रक्रियाओं को काफी बेहतर बना सकते हैं।

उदाहरण के लिए, जहाँ भारत ऑस्ट्रेलिया के विशाल लिथियम और कोबाल्ट भंडारों तक अपनी पहुँच बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार यहां के महत्वपूर्ण खनिजों तक भारत की पहुँच को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यामिनी अग्रवाल इस पर लिखती हैं, भारत-ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य आवश्यक खनिजों की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। सहयोग के नज़रिए से दोनों देश अधिक विविध और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला बनाना चाहते हैं, जिससे उनकी किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके।

जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश अपने महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात से राजस्व में वृद्धि का लाभ उठा रहे हैं, वहीं मलेशिया और भारत जैसे देश इस उछाल का लाभ उठाने की योजनाएँ बना रहे हैं, साथ ही खनन से होने वाले पर्यावरणीय जोखिमों को संतुलित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मलेशिया की राष्ट्रीय खनिज उद्योग परिवर्तन योजना 2021-2030, जिसे 2021 में शुरू करने का उद्देश्य पूरे मूल्य श्रृंखला में राष्ट्रीय खनिज उद्योग का सतत विकास करना है, ताकि यह देश विकास का नया स्रोत बन सके। देश में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडारों का मूल्य 160 अरब अमेरिकी डॉलर तक आंका गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में निवेश करना राजनीतिक दृष्टि से भी तर्कसंगत है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच जारी तनावों ने ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुँच के महत्व को और बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, मुक्त बाजार की नीतियों से हटकर औद्योगिक नीतियों की ओर वापसी देखने को मिल रही है, जैसे कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, यूरोपीय संघ का क्रिटिकल रॉ मैटीरियल्स एक्ट, और फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया एक्ट शामिल है। इन्ही दुर्लभ खनिज संसधानों के ज़रिए दुनिया का हर देश अपनी कूटनीतिक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलना चाहता है।

विश्व क्रिकेट का संकट, खेल या सियासत?

खेल

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तंभकार हैं।

क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। जब बल्ला और गेंद की टकराहट से उठने वाली आवाज़ सीमाओं के पार जाकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती है, तब क्रिकेट मैदान केवल खेल का मंच नहीं रहता, बल्कि वह राजनीति, कूटनीति और जनभावनाओं का संगम बन जाता है। ऐसे में जब किसी देश द्वारा खेल से हटने जैसा फैसला लिया जाता है, तो वह केवल खेल का मामला नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक हितों और खेल भावना के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मुकाबले से पाकिस्तान के हटने का निर्णय इसी तरह का एक घटनाक्रम है, जिसने विश्व क्रिकेट में नई कटुता और असहजता पैदा कर दी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का इतिहास हमेशा से रोमांच, भावनाओं और विवादों से भरा रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का असर अक्सर खेल पर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट कई बार संवाद और सौहार्द्र का माध्यम भी बना है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का निर्णय लिया, तो यह फैसला केवल एक खेल से पीछे हटने का नहीं, बल्कि खेल को राजनीतिक हथियार बनाने की मानसिकता का प्रतीक बन गया। सबसे अधिक निराशाजनक बात यह रही कि इस निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। जब बिना कारण खेल से दूरी बनाई जाती है, तो यह संदेह और अविश्वास को जन्म देता है, जो खेल के मूल उद्देश्य के विपरीत है।

क्रिकेट की वैश्विक संरचना में भारत की भूमिका आज निर्विवाद रूप से केंद्रीय है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड न केवल आर्थिक रूप से सबसे मजबूत संस्था है, बल्कि विश्व क्रिकेट के संचालन में भी उसकी भूमिका निर्णायक है। प्रसारण अधिकारों से लेकर प्रायोजन तक, भारतीय दर्शकों की भागीदारी विश्व क्रिकेट की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान का यह रवैया कि वह भारत के साथ खेलने से इनकार करे, केवल भावनात्मक या राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आत्मघाती प्रतीत होता है। यह विडंबना ही है कि जिस विश्व क्रिकेट को भारत की भागीदारी से सबसे अधिक लाभ मिलता है, उसी मंच पर भारत के खिलाफ खेलने से इंकार किया जाए।

पाकिस्तान क्रिकेट पर राजनीति का प्रभाव कोई नया तथ्य नहीं है। वहां खेल अक्सर सत्ता की रणनीतियों और राष्ट्रीय भावनाओं के दबाव में संचालित होता रहा है। 2008 के बाद भारतीय टीम का पाकिस्तान न जाना आतंकवाद और सुरक्षा चिंताओं का परिणाम था, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी काफी हद तक समझा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के शासक वर्ग ने कभी आत्ममंथन नहीं किया कि आखिर उनके देश की परिस्थितियां ऐसी क्यों बनीं कि अंतरराष्ट्रीय टीमें वहां खेलने से कतराने लगीं। इसके उलट, उन्होंने हर बार खेल को भारत विरोधी राजनीति का मंच बना दिया। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन यह नुकसान भी उनके राजनीतिक आग्रहों को बदलने में सक्षम नहीं हो सका।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला केवल दो टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों की भावनाओं का उत्सव होता है। यही कारण है कि इस मैच के दौरान विज्ञापन दरें आसमान छूने लगती हैं और प्रसारण कंपनियों को अभूतपूर्व लाभ होता है। यह आर्थिक पहलू केवल निजी कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे विश्व क्रिकेट के ढांचे को भी मजबूती मिलती है। जब पाकिस्तान इस मुकाबले से हटता है, तो वह न केवल खेल भावना को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आईसीसी और आयोजकों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा कर देता है। यह कदम यह संकेत देता है कि पाकिस्तान खेल को सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बजाय विरोध और टकराव का माध्यम बनाना चाहता है।

इस पूरे घटनाक्रम को बांग्लादेश के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने यह संकेत दिया कि वह खेल के बजाय राजनीतिक एकजुटता को प्राथमिकता दे रहा है। यह स्थिति खेलों के मूल उद्देश्य के विपरीत है। खेलों का उद्देश्य राष्ट्रों को जोड़ना, संवाद बढ़ाना और सांस्कृतिक निकटता को मजबूत करना होता है। जब खेल को भू-राजनीतिक रणनीति का उपकरण बना दिया जाता है, तो वह अपने मूल स्वरूप को खो देता है और संघर्ष का मंच बन जाता है।

आईसीसी के सामने यह स्थिति एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। यदि कोई देश राजनीतिक कारणों से खेल से पीछे हटता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आईसीसी ऐसे मामलों में स्पष्ट और कठोर नीति अपनाए, ताकि भविष्य में कोई भी देश खेल भावना के साथ खिलवाड़ न कर सके। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति अन्य देशों में भी फैल सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय खेलों का भविष्य संकट में पड़ सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति आत्मसम्मान और नीति निर्धारण का प्रश्न बन गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब यह तय करना होगा कि वह केवल आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देगा या राष्ट्रीय सम्मान और खेल की गरिमा को भी समान महत्व देगा। भारत की भलमनसाहत का प्रमाण यह रहा है कि उसने हमेशा खेल को राजनीति से ऊपर रखने की कोशिश की है। लेकिन जब इस उदारता का उत्तर बार-बार विरोध और अपमान के रूप में मिलता है, तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है।

अब यह सोचने वाली बात है कि खेल और राजनीति के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। यह सत्य है कि खेल पूरी तरह राजनीति से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि खिलाड़ी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और खेल राष्ट्र की पहचान का हिस्सा होता है। लेकिन जब राजनीति खेल पर पूरी तरह हावी हो जाती है, तो खेल अपनी आत्मा खो देता है। इसलिए आवश्यक है कि खेलों को संवाद और सहयोग का माध्यम बनाया जाए, न कि टकराव और कटुता का। भारत-पाकिस्तान क्रिकेट विवाद केवल दो देशों के बीच खेल का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह वैश्विक खेल संस्कृति के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि खेल को राजनीति का बंधक बना दिया गया, तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। भारत को चाहिए कि वह अपनी आर्थिक शक्ति और नैतिक प्रभाव का उपयोग करके विश्व क्रिकेट में संतुलन और न्याय की स्थापना करे। वहीं पाकिस्तान को भी यह समझना होगा कि कट्टर राजनीति से न तो खेल का भला होता है और न ही राष्ट्र का।

क्रिकेट का मैदान संघर्ष का नहीं, संवाद का मंच होना चाहिए। बल्ला और गेंद की टकराहट से उठने वाली गूंज नफरत नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और सम्मान की भावना पैदा करे, यही खेल की सच्ची आत्मा है। यदि विश्व क्रिकेट इस आत्मा को बचाए रखने में सफल होता है, तभी खेल अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। अन्यथा, क्रिकेट भी राजनीति की कटुता में उलझकर अपनी पहचान खो देगा, और यह नुकसान केवल किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व खेल समुदाय का होगा।

सप्तसागरों को बचाने आगे आया एनजीटी

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने
लेखक जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

देश में मध्यप्रदेश के केवल उज्जैन में ही सप्तसागर है, जिसका अपना धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। दिनोंदिन इन सप्त सागरों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। प्रत्येक सागर में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसी प्रकार इन पौराणिक सागरों में गंदा पानी मिलने से जिला प्रशासन और नगर निगम रोक नहीं लगा पा रहा है। ऐसी हालत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) इन प्रसिद्ध सप्तसागरों पर से अवैध कब्जे हटाने और गंदा पानी मिलने से रोकने आगे आया है।

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल ने उज्जैन के इन सप्तसागरों को बचाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए है। एनजीटी ने ये देखा है कि गोवर्धन सागर सहित सभी जलाशयों में अवैध कब्जा हो गया है और गंदा पानी इन सागरों में मिल रहा है। इन सप्तसागरों में से एक सागर तो सागर नहीं रहा बल्कि कुंड सा बन गया है। इसकी दुर्दशा सबसे अधिक है। पुराणों में भी इन सप्तसागरों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति श्री एस.के सिंह और विशेषज्ञ सदस्य श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी थे। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि 36 बीघा क्षेत्र में से 18.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। यानी सागर की आधी जगह में कब्जा हो चुका है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि पहले उज्जैन नगर निगम और जिला प्रशासन को जो निर्देश दिए थे, उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। इस पर एनजीटी ने सख्त टिप्पणी भी की।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि उज्जैन के इन प्रसिद्ध जलाशयों से अवैध कब्जा हटाया जाए। इसके साथ ही इन सभी सप्तसागरों में मिल रहे गंदे पानी को रोकने की सख्त कार्रवाई की जाए। एनजीटी ने पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सप्त सागरों की मासिक निगरानी करने और जल की गुणवत्ता की भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी ने 12 साल में एक बार उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के भव्य आयोजन को देखते हुए इन जलाशयों की पवित्रता और पानी की शुद्धता बनाए रखने का महत्व भी प्रतिपादित किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी साधु संतों ने सप्तसागरों की पवित्रता बनाए रखने और अतिक्रमण रोकने के लिए अनेक बार जिला प्रशासन से अनुरोध भी किया था। एक बार तो साधु संतों ने सप्तसागरों की सुरक्षा के लिए धरना आंदोलन भी किया था, किन्तु हुआ कुछ विशेष नहीं ! आज भी सप्तसागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं।

सप्तसागरों में से एक प्रसिद्ध रूद्रसागर है। यह महाकाल मंदिर से लगा हुआ होने के कारण से भी अपना विशेष महत्व रखता है। किन्तु इस पर भी अवैध अतिक्रमण हो गया। निजी अतिक्रमणकारियों के अलावा शासकीय स्तर पर भी इस पर अतिक्रमण किया गया। वर्ष 2016 के सिंहस्थ के समय सप्तसागर पर ही त्रिवेणी संग्रहालय बना दिया गया। यह संग्रहालय रूद्रसागर के करीब आधे पानी पर ही अतिक्रमण करके बनाया गया। इसके बाद भव्य महाकाल लोक बनाया गया। इस रूद्र सागर के किनारे-किनारे ही महाकाल लोक बनाया गया। महाकाल लोक ने भी रूद्र सागर को छोटा कर दिया। सरकार के ही विभाग मिलकर यदि रूद्रसागर पर अतिक्रमण कर निर्माण करेंगे तो उसे कौन रोकेगा ?

आइये, अब हम देखते हैं इन पौराणिक सप्तसागरों का महत्व क्या है ? अधिक मास का महत्व मानने वाले श्रद्धालु धर्म के मान से धार्मिक यात्रा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उज्जैन के सप्तसागर, नौ नारायण और चौरासी महादेव की यात्रा फलदायी बताई गई है। सप्त सागर दर्शन के स्थान एवं दान सामग्री की जानकारी इस प्रकार बताई गई है -

रुद्रसागर, यह उज्जैन में माँ हरसिद्धि की पाल पर स्थित है। वहाँ पर नमक, श्वेत वस्त्र, चाँदी के नंदी की मूर्ति का दान का महत्व बताया गया है। पुष्कर सागर, ये नलिया बाखल में स्थित है और इसमें पीला वस्त्र, चना दाल, स्वर्णदान किया जाता है। क्षीरसागर, नई सड़क पर बसा है। यहाँ साबूदाने की खीर और पात्र दान किया जाता है। गोवर्धन सागर, निकास चौराहा पर स्थित है। यहाँ पर माखन, मिश्री, पात्र में गेहूँ और लाल वस्त्र दान करना शुभ माना गया है।

मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव उज्जैन के ही है। और उज्जैन दक्षिण क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य है। वे सप्तसागरों का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे अब सप्तसागरों पर भी ध्यान केन्द्रित करें। वे सबसे पहले सप्तसागरों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर प्रत्येक सप्तसागरों के आसपास बाउंड्रीवाल बनवाए, ताकि भविष्य में कोई अतिक्रमण न हो सके। इसके साथ ही इन सागरों में मिल रहे गंदे पानी को रोकने का स्थायी बंदोबस्त किया जाए, ताकि इसकी शुद्धता और पवित्रता बनाई रखी जा सके। ऐसा होगा तो ही सप्तसागरों को बचाया जा सकेगा अन्यथा दिनोंदिन इन सप्तसागरों पर अतिक्रमण बढ़ता ही जायेगा और एक दिन ऐसा आयेगा कि वे लुप्त हो जायेंगे !

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बजट की खटिया पर सोया आम आदमी

व्यंग्य

मुकेश राठौर
लेखक व्यंग्यकार हैं।

'सरग दिदा पाणी दे,पाणी दे।' जिस तरह चातक आसमान की ओर टकटकी लगाए स्वाति बूंद को तरसता है,बजटकाल मे वही हालत नौकरीपेशा की होती है कि आयकर में छूट की कुछ बूंदे बरसे और वह सरकारी नलके से भरे घड़े से लोटा भर सरकार को लौटाने से बच जाए। हर बार आयकर का दायरा बढ़ता है बावजूद वह आयकर की मार से नहीं बच पाता। परछाई के पीछे भागने जैसा खटकरम। राष्ट्रहित में कड़े फैसले लेने वाली कड़क सरकार से लेकर जनहित में नरम फैसले लेने वाली नरम सरकारें अपने-अपने बजट पेश करती है। आम जनता चाहती है नए साल में कुछ तो नया हो। रोजमर्रा की वस्तुओं के मूल्य घटे ताकि महंगाई की मार से आहत की सांस लेते लोग कुछ तो राहत की सांस लें। अफसोस सरकार चने देती है तो दांत छीन लेती है और दांत देती है तो चने 'घोड़े' खा जाते हैं। सरकारें बजट में सिगरेट के भाव बढ़ाती है तो मोबाइल के दाम घटा देती है। देश का युवावर्ग कन्फ्यूज है अपने फेफड़े बचाए या दिलोदिमाग...? चरित्र तो खैर बाद की बात है। हालांकि मोबाइल के दाम घटाने के पीछे सरकार की मंशा देशवासियों को सूचना संपन्न बनाना है क्योंकि सूचना क्रांति के दौर में आज वही संपन्न है जिसके पास अधिकाधिक सूचनाएं हैं। सूचनाओं से पेट भरे न भरे कान जरूर भरे जा सकते हैं। इतने की कोई कुछ दूसरा भरना भी चाहे तो भरा न जा सकें।

देश प्रदेश के वित्तमंत्री शेर पढ़कर बजट भाषण पढ़ते हैं। यही परंपरा है। टीवी पर बजट का विश्लेषण करने वाले एंकर और अर्थशास्त्री भी अक्सर मिर्जा गालिब का 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मिरे अरमान फिर भी बहुत कम निकलें' सरीखे शेर पढ़ते हैं। अखबारों में संपादकीय लिखने वाले भी। यह शेरों का समय है। अब बजट भाषण पढ़ो, कथा पढ़ो या शोक संदेश...एकाध शेर न छोड़ा तो कुछ अधूरापन लगता है। शेर छोड़ना ही चाहिए कूनो में छोड़ों,कोनों में या कि कानों में...! शेर ओ शायरी न करो तो दुनिया लघुकथाकार समझ बैठती है।

अबके नौवीं बार वित्तमंत्री महोदया ने बजट पेश किया। काश कि घर में बजट पेश करने की परम्परा होती, तो हम उनसे कहीं आगे होते। खैर,बजट पूर्व हर बार की तरह हलुआ सेरेमनी हुई और हलुआ खिलाकर टीम बजट को 'लॉक-इन' कर दिया ताकि बजट आने तक गोपनीयता बनी रहे। इंसानी स्वभाव है गोपनीयता भंग करने में उसे मजा आता है। बजट आया तो पाया कपड़े,जूते सस्ते हो गए। ये बात और है कि आटे-दाल के हाल वही रहें। पच्चीस करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। आना ही था। पहले सौ दिन और अब सवा सौ दिन रोजगार जो मिलने लगा। बजट हर एंगल से गरीब हितैषी है। सिगरेट के मुकाबले बीड़ी सस्ती हो गई। हुआ न गरीब हितैषी। पक्ष ने इसे विकास को पर लगाने वाला तो विपक्ष ने इसे खाली डब्बा कहा। वह अड़ गया। विपक्ष का अड़ना लाजिमी है। 'जो रूठे न वह फूफा नहीं और जो अड़े न वह विपक्ष नहीं।

नए बजट भाषण पर पुरानी और पुराने बजट भाषण पर हो रही नई चर्चा के बीच विचारता हूं 'आम बजट की खटिया पर आम आदमी सिरहाने सिर करके सोए या पायताने... उसकी कमर तो बीच ही रहनी है।' और फिर ये तो सबको पता है महंगाई और कमर की लड़ाई में टूटना हमेशा कमर को ही है।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

आधुनिक कृषि की चुनौतियां, किसान हित और जीएम बीजों का भविष्य

अक्सर देखा गया है कि कीटों के प्रकोप के समय बाजार में कीटनाशकों की कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है और उन्हें मनमाने दामों पर बेचा जाता है। विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की तरह कीटनाशकों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। इससे किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद मिलेगी। मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम कीमत के नाम पर किसानों को नकली या मिलावटी कीटनाशक न दिए जाएं। इसके लिए 'ट्रैसेबिलिटी' यानी कारखाने से खेत तक की निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए।

भारतीय कृषि आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ उत्पादकता बढ़ाने के दबाव और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया है। 1968 के पुराने 'कीटनाशक अधिनियम' को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित 'कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025' (पीएमबी 2025) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, यह विधेयक केवल रसायनों के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की खेती, बीजों की तकनीक और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला है। विशेष रूप से जीएम बीजों का कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण और कॉर्पोरेट जवाबदेही जैसे मुद्दे इस बहस के केंद्र में हैं।

विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा वाली बात इसकी व्यापक परिभाषा है। दस्तावेज़ों के अनुसार, 'टॉक्सिन-संबंधित जीन संशोधन' को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर बीटी (Bt) कपास या बीटी बैंगन जैसी फसलों पर पड़ेगा।

1. **कीटनाशक के रूप में वर्गीकरण-** वर्तमान में, जीएम बीजों को मुख्य रूप से 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' और बीज नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। लेकिन PMB 2025 के तहत, यदि कोई बीज स्वयं कीटों से लड़ने वाला 'जहर' पैदा करता है, तो उसे एक 'कीटनाशक उपकरण' या स्वयं कीटनाशक के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीज कंपनियों को अब न केवल बीज मानकों का पालन करना होगा, बल्कि कीटनाशक पंजीकरण समिति से भी कड़े सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने होंगे।
2. **जवाबदेही और नियामक जांच-** यदि किसी जीएम फसल के कीटनाशकीय गुणों के कारण मिट्टी के मित्र कीटों (जैसे केंचुए या मधुमक्खियां) को नुकसान पहुँचता है या मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। यह 'कॉर्पोरेट लायबिलिटी' के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ अब कंपनियां केवल यह कहकर नहीं बच सकतीं कि उन्होंने केवल बीज बेचा है।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत का एक बड़ा हिस्सा कीटनाशकों और उर्वरकों पर खर्च होता है। विधेयक में 'मूल्य नियंत्रण' को शामिल करने की मांग किसानों के अस्तित्व से जुड़ी है।

मूल्य निर्धारण की आवश्यकता- अक्सर देखा गया है कि कीटों के प्रकोप के समय बाजार में कीटनाशकों की कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है और उन्हें मनमाने दामों पर बेचा जाता है। विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की तरह कीटनाशकों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। इससे किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद मिलेगी।

गुणवत्ता का आश्वासन- मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि कम कीमत के नाम पर किसानों को नकली या मिलावटी कीटनाशक न दिए जाएं। इसके लिए 'ट्रैसेबिलिटी' यानी कारखाने से खेत तक की निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए।

कीटनाशक जहर राहत कोष- मानवीय संवेदना और न्याय

खेती के दौरान कीटनाशकों के संपर्क में आने से हर साल हजारों किसान और मजदूर बीमार होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। प्रस्तावित धारा 44a के तहत एक 'कीटनाशक जहर राहत कोष' बनाने का सुझाव दिया गया है।

अनिवार्य मुआवजा- इस कोष का निर्माण कीटनाशक कंपनियों के योगदान से किया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कीटनाशक के कारण सामूहिक बीमारी या आकस्मिक मृत्यु होती है, तो इस कोष से पीड़ितों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए।

बिना दोष के उत्तरदायित्व- राहत पाने के लिए किसान को यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कंपनी ने जानबूझकर गलती की है। यदि उत्पाद के उपयोग से नुकसान हुआ है, तो कंपनी को मुआवजा देना ही होगा।

विधेयक में सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता की मानी गई है। वर्तमान में, कीटनाशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कमरों में होती है, जहाँ केवल सरकारी अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं।

सार्वजनिक परामर्श- प्रस्तावित सुधारों में यह मांग की गई है कि किसी भी नए कीटनाशक को मंजूरी देने से पहले उसके विष विज्ञान डेटा को सार्वजनिक किया जाए और किसानों, वैज्ञानिकों व नागरिक समाज से आपत्तियां मांगी जाएं।

सूचना का अधिकार- किसान को यह जानने का पूरा हक है कि वह जो रसायन अपने खेत में डाल रहा है, उसका मिट्टी और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। पंजीकरण समिति को अपने हर निर्णय का लिखित कारण और वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक पोर्टल पर साझा करना चाहिए।

विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य 'पर्यावरण-मित्र' कृषि को बढ़ावा देना होना चाहिए। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि-

जैव-कीटनाशकों को प्रोत्साहन- नीम, गौमूत्र और अन्य जैविक अर्क पर आधारित कीटनाशकों को पंजीकरण में छूट और सब्सिडी मिलनी चाहिए।

राज्यों को अधिकार- चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर किसी विशेष खतरनाक कीटनाशक को प्रतिबंधित कर सकें।

अंततः कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 भारत की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच एक सेतु बन सकता है। जीएम बीजों की सख्त निगरानी, कीटनाशकों के मूल्यों पर लगाम, और पीड़ितों के लिए तत्काल राहत कोष जैसे प्रावधान इस कानून को वास्तव में 'किसान-हितैषी' बनाएंगे। संसद को चाहिए कि वह प्रस्तावित 54 संशोधनों पर गंभीरता से विचार करे ताकि यह विधेयक केवल कागजों पर न रहे, बल्कि खेतों में हरियाली और किसान के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित करे। यदि हम आज एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा तैयार नहीं करते, तो भविष्य की पीढ़ियों को जहरीली मिट्टी और असुरक्षित भोजन विरासत में मिलेगा।

लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था का पर्याय है बजट

बजट 2026

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

2026-27 का केंद्रीय बजट मुनीम साहब की खाता-बही है। जिसमें ना कोई दिशा है-ना कोई जनहितकारी बड़े उपाय हैं-ना कोई उम्मीद है। बस केवल आवक-जावक दर्ज हैं। कहने को सबका साथ और सबका विकास है। परंतु, वास्तव में कॉर्पोरेट का साथ और बाकी सबका विनाश है।

देश की कुल आय में कॉर्पोरेट की टैक्स हिस्सेदारी कम है और आमजन की टैक्स हिस्सेदारी ज्यादा है। जबकि, होना यह चाहिए था कि कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ाकर आमजन को राहत दी जाती। कुल मिलाकर यह बजट यथास्थिति का बजट है। डेटा कंपनियों को आगामी 22 वर्ष के लिए टैक्स होलीडे यानि टैक्स की छूट दे दी गई है। देश को उम्मीद थी कि सरकार आयुष्मान की व्यवहारिक कमियों को देखकर या तो उसे संशोधित करती या फिर चिकित्सा का मूल अधिकार बनाकर आमजन को आवश्यक और पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराती। उच्च शिक्षा के नाम पर सरकार ने विदेश में यात्रा, पढ़ाई और पैसे भेजने पर जो 10 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत टैक्स था और 10 लाख से ऊपर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे घटकर 2 प्रतिशत कर दिया है। निःसंदेह इससे विदेश में जाकर पढ़ने वालों को सुविधा होगी। परंतु, भारत की शिक्षा के लिए चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, कोई प्रावधान नहीं है और उन्हें खुले बाजार पर छोड़ दिया गया है। सरकारी स्कूल जो शिक्षकों के अभाव में बंद हो रहे हैं, उसके लिए भी, कोई उपाय नहीं किए हैं तथा शिक्षा के बजट का बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों तथा यूनिवर्सिटी टाउनशिप आदि पर खर्च होगा। कालेधन संचय करने वालों के प्रति सरकार मेहरबान है और विदेशों में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए तक की संपत्ति की जानकारी नहीं देता तो उसे पहले जो जेल में जाने का प्रावधान था, वह, अब नहीं होगा। यह काले धन के मालिकों के लिए काला-धन छुपाने की खुली छूट होगी। सरकार ने देश को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय किया है। परंतु, इसके लिए देश के 500 शहरों में से 50 शहर चिन्हित किए हैं यानि गांव, कस्बा और छोटे शहरों को छोड़कर केवल महानगरों का ही विकास होगा। रोजगार के नाम पर भी केवल दिखावटी और प्रचारात्मक निर्णय किया गया है। वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। अब ये 20 लाख पेशेवर कौन लोग होंगे और क्या ये पेशेवर रोजगार का विकल्प होंगे? 1.5 (डेढ़) लाख केयर-गिवर्स के नाम के पदधारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केयर-गिवर्स का वास्तविक अर्थ होगा मेल-नर्स और जो उच्च तबके के संपन्न, लाखों की पेंशन पाने वाले, उच्च घरों में उनकी व्यक्तिगत देखभाल करेंगे और घरेलू कर्मचारियों के समान वेतन पाएंगे। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? शोध का विषय है! ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफ-वार और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से घायल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जो ना खड़ी हो सकती है और ना ही चल सकती है। यह सरकार का लकवाग्रस्त बजट है।

आरामतलबी बढ़ा रही घर पहुंच सेवाएं

आधुनिकता

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

अलसुबह अलसाये हुए जागने पर चाय कॉफी की तलब लगना आज के भाग-दौड़ वाले जीवन की अनिवार्य जरूरत बन गई है। ऐसे में यदि घर के किचन में चाय की पत्ती, कॉफी या अदरक खत्म हो जाये तो फौरन ब्लिंकिट किया जाता है। थोड़ी देर में ही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देकर ये चीजें उपलब्ध करा देता है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला इतना भी कष्ट क्यों उठाया जाये तो 'चाय कप्पी' से जोमेटो के जरिये गर्मागर्म चाय भी कुछ ही समय में करीने से सजकर आ सकती है। ऐसी ही अन्य सेवायें आजकल उपलब्ध है। हालांकि हाल ही में दस मिनट में डिलिवरी का सिस्टम खत्म होने की बात सामने आई थी लेकिन इस पर कितना अमल हो रहा हम नहीं जानते।

सो, यह सब आज की जनरेशन खास तौर पर विद्यार्थियों, जेन- जी, कामकाजी और नव दम्पत्ति के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास इन उलझनों के लिए ना तो वक्त रहता है और ना ही खुद बनाकर खाने की इच्छा। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि घर में क्या चीजें हैं क्या नहीं। लेकिन यह भी सच है कि क्विक कामर्स प्लेटफार्म और ऑनलाइन सेवायें हमें कहीं आरामतलबी तथा व्यर्थ के आलस्य की ओर तो नहीं ले जा रही?

बीते दिनों देश के आम बजट से पूर्व आये आर्थिक सर्वे में जंक फूड (चीनी, वसा, नमक आदि की अधिकता वाले) की बढ़ती खपत पर चिंता जाहिर की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के एड पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। इसी प्रकार छोटे बच्चों, शिशुओं के लिए प्रयुक्त दूध और और अन्य पेय पदार्थों के प्रचार-प्रसार पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई है। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी फिक्रमंद होने को कहा गया है। अब इन पर अमल कब कितना होता है यह आने वाला वक्त ही बतायेगा। हालिया सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंक फूड और डिजिटल एडिक्शन को खासकर युवा आबादी के लिये जोखिम उत्पन्न होने का खतरा बताया गया है। कहा गया है कि जंक फूड के बढ़ते मार्केट और खपत मोटापे को बढ़ा रही है जो स्वास्थ्य के लिये मुफीद नहीं है।

इस बीच पिछले दिनों खबर आई कि अब दस मिनट में डिलीवरी का सिस्टम या बाध्यता समाप्त होने जा रही है। अच्छा ही हुआ कि सड़कों, सकरे रास्तों पर बाइक से कूदते फांदते, कभी सर्कस जैसे स्टंट या करतब दिखाते डिलीवरी बॉय शायद अब ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके चलते सुगम ट्राफिक के संचालन में कितनी मदद मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि सड़कों पर बेतरतीब ट्राफिक तथा तेज गति से वाहन चलाने हेतु सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं बल्कि शीघ्र पहुंचने की मंशा और नियमों की अनदेखी ट्राफिक को अस्त व्यस्त कर देती है।

उधर हाल ही में ब्लिंकिट जैसी क्विक कामर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी की अनिवार्यता हटाने पर सहमति जताई है। यानी आर्डर करने के 10 मिनट में डिलीवरी बॉय की प्रतीक्षा अब बेमानी हो जाना चाहिये। इसे लेकर ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी समेत प्रमुख प्लेटफार्म के साथ संपन्न बैठकों में इस स्थिति से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई थी।

बीते माह तकरीबन 22 शहरों में गिग वर्कर्स ने हड़ताल की थी। उनकी यूनियन का कहना था कि कंपनियां 10 मिनट की डिलीवरी के नाम पर कथित शोषण कर रही है। औसतन बारह- चौदह घंटे काम करने पर भी कई वर्कर्स 25 हजार रुपए से भी कम पाते हैं। इसके चलते वे ओवर टाइम तथा सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

आजकल चाइनीज, जंक, प्रोसेस्ड फूड आदि का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। सो, इसमें पास्ता, मेगी, बर्गर, नूडल्स, मोमोस, वेज बिरयानी जैसे अन्य फूड की घर पहुंच सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। यहीं नहीं साऊथ इंडियन डिशेज और खाने के टिफिन की भी होम डिलेवरी सुलभ है। बस आप इच्छा तो व्यक्त कीजिये, हाजिर है।

इनके अतिरिक्त ग्रॉसरी, रेडीमेड कपड़े, सलवार कुर्तियां, किड्स के साथ बड़ो के शर्ट, टीशर्ट, जीन्स, लोअर, बरमूड़ा, गर्म कपड़े और कुछ तो भी डिजाइन के कपड़े सहज ही ऑनलाइन उपलब्ध है। घर बैठे आर्डर कीजिये बस, यह व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है। इससे भी एक कदम आगे आकर कुछ कंपनियां पसंद नहीं आने पर या गलत साइज पर वापसी (लौटाफेरी) की गारंटी भी दे रही है। एक बार नहीं अनेक मर्तबा लौटाफेरी की जा सकती है। इस धंधे में फ्लिप कार्ड, अमेजन, मिंत्रा जैसी नामी कंपनियां शामिल है। अब इस बात का सर्वे करने की जरूरत है कि घर पहुंच सेवाओं का इन वस्तुओं के परंपरागत विक्रेताओं के व्यवसाय पर कितना और कैसा असर पड़ रहा है। ग्रॉसरी सामान की लिस्ट ऑनलाइन भेज दीजिये, सामान घर पहुंच जायेगा। जहां तक परंपरागत शॉप्स, शोरूम, बड़े प्रतिष्ठान का मामला है वे तो खरीदी गई वस्तुओं की लौटाफेरी करते नहीं बल्कि तख्ती पर अंकित होता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। सो, बाजार का स्वरूप भी बदल रहा है इसमें आप और हम कहाँ एडजस्ट होते हैं इसकी फिक्र कीजियेगा।

सुखी एवं समृद्ध दुनिया का आधार है बंधुत्व भाव

सुंदर एवं समझ-बूझ भरी दुनिया बनाने का सपना केवल पारस्परिक बंधुत्व भाव से ही सम्भव है। समतामूलक ममतायुक्त दुनिया की निर्मिति प्रेम-स्नेह, सहयोग एवं भाईचारे की सामूहिक सामाजिक चेतना से ही सम्भव है। इसी भावना से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को एक प्रस्ताव पारित कर 4 फरवरी को सम्पूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, नागरिक संगठनों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं को आमंत्रित किया, जिसका स्वागत विभिन्न देशों सहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक-आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा किया गया और 4 फरवरी, 2021 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मना कर मानवता के पक्ष में कार्य करने, दुनिया में कहीं भी किसी भी मनुष्य के प्रति रंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने, मानवोचित गरिमामय व्यवहार करने तथा सहिष्णु समाज बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया।

अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समान अधिकारों और करुणा पर आधारित हो और एक मानव परिवार के रूप में शांति से रह सकें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का यह कथन भारतीय मनीषा के बोधवाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अद्यतन व्याख्या ही है जिसमें एक शांतिपूर्ण, सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और तमाम भेद-भावों से मुक्त सुंदर दुनिया रचने की मार्मिक अपील समाहित है। सुंदर एवं समझ-बूझ भरी दुनिया बनाने का सपना केवल पारस्परिक बंधुत्व भाव से ही सम्भव है।समतामूलक ममतायुक्त दुनिया की निर्मिति प्रेम-स्नेह, सहयोग एवं भाईचारे की सामूहिक सामाजिक चेतना से ही सम्भव है। इसी भावना से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को एक प्रस्ताव पारित कर 4 फरवरी को सम्पूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, नागरिक संगठनों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं को आमंत्रित किया, जिसका स्वागत विभिन्न देशों सहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक-आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा किया गया और 4 फरवरी, 2021 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मना कर मानवता के पक्ष में कार्य करने, दुनिया में कहीं भी किसी भी मनुष्य के प्रति रंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने, मानवोचित गरिमामय व्यवहार करने तथा सहिष्णु समाज बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया।

यह संसार अत्यंत विशाल है। यहां विभिन्न संस्कृतियों को मानने-जीने वाले समुदाय युगों-युगों से निवास कर रहे हैं। इनमें परस्पर खान-पान एवं पहनावा, बोल-चाल एवं व्यवहार तथा आस्था, विश्वास एवं मान्यताओं में अंतर देखने को मिलता है। एक समुदाय के लिए उनके रीति-रिवाज एवं परम्परा अनुसार जो उचित, नैतिक एवं अनुकूल है, सम्भव है वह पद्धति दूसरे समुदाय के विश्वासों की धुरी पर अनैतिक, अनुचित एवं प्रतिकूल हो। ऐसी स्थिति में टकराव स्वाभाविक है, पर बेहतर समझ होने पर टकराव एवं द्वंद्व से बचते हुए और अपनी परम्पराओं का पालन करते हुए साथ-साथ न केवल रहा जा सकता है बल्कि विकास के सामूहिक अवसर भी खोजे-बनाये जा सकते हैं। समुदायों के आस्था एवं विश्वास टकराव का हेतु न बनकर सामंजस्य एवं सौहार्द का सेतु बनें, यह बंधुत्व भाव के विकसित होने पर ही सम्भाव्य है। और इसके लिए आवश्यक है विवेकपूर्ण चिंतन-मनन और दूरदृष्टि, जो मानवता के फलक पर समभाव एवं सद्भाव के लिए सुंदर सुनहरे चित्र उकेर सके। सतत विकास और बौद्धिक प्रखरता के लिए मतभेद जरूरी हैं, किंतु हमारी असहमति किसी दूसरे पक्ष के जान-माल की हानि से संतुष्ट हो, यह बिलकुल निरर्थक, अव्यावहारिक एवं अस्वीकार्य है। असहमतियों से हमारे वैचारिक पृष्ठों पर उज्ज्वलता का आलोक बिखरना चाहिए, न कि दूसरे का अनिष्ट करने के कलुष धब्बे। एक व्यक्ति एवं परिवार के रूप में प्रत्येक समुदाय एवं हममें से सभी सुखी, शांतिमय एवं समृद्ध होना चाहते हैं और यह तभी साकार हो सकेगा जब हम एक-दूसरे को सुखी-समुन्नत एवं प्रसन्न देखना चाहें। यह सहयोग, समन्वय, सहकार के सम्बल से किया जा सकता है, यही संस्कृति है। किंतु टकराव के रास्ते चलकर परस्पर लड़ते-झगड़ते और दूसरे को दुखी करके, नीचा दिखा अपमानित कर हम कभी अपना हित नहीं साधक सकते, यही विकृति है, अमानवीयता है। निर्णय हमें करना होगा कि हम किस पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। निर्विवाद कहा जा सकता है, सभी मानवता के उद्यान में शीतल मलय बयार एवं सुगंधित सुमनों के सुरभित परिवेश में विचरण करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यही भाव विकसित करने के लिए लोक जागरण करते हुए विभिन्न समुदायों एवं जन-जन को शांतिपूर्वक एक साथ रहने, एक-दूसरे के अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा करने एवं मानवीय व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

बंधुत्व भावना केवल अन्यान्य समुदायों के साथ ही नहीं अपितु प्रथमतः अपने परिवारी जन, पड़ोसी, सहकर्मियों एवं अपरिचितों के प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यह हमें सर्व समावेशी, सख्य, सहिष्णु एवं लचीला बनाता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता की सहज स्वीकृति एवं अभिव्यक्ति के अनुकूल अवसर एवं जगह बनती है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य देखें तो सर्वत्र हिंसा, अराजकता, आगजनी, युद्ध, विभीषिका के दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो मानवता के लिए अभिशाप हैं। मुझे यूनेस्को का एक कथन स्मरण हो रहा है, 'चूंकि युद्ध मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा भी मनुष्य के मन में ही निर्मित होनी चाहिए।' निश्चित रूप से युद्ध और शांति मानव मन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। विश्व के समस्त प्राणियों में मानव ही सर्वाधिक बुद्धिमान है। पर जब वह विवेकहीन हो स्वार्थ केंद्रित हो जाती है तो अनीति की पक्षधर बन मानवता के सुकोमल सुमनों को कुचलने लगती है। और तब यह दम्भ, अहंकार, हिंसा, बलात कब्जा, स्व श्रेष्ठताबोध और संसाधनों पर अपने एकाधिकार करने का प्रदर्शन बन जाती है। अनेकानेक उदाहरण जागतिक फलक पर वर्तमान हैं। इनसे मुक्ति का मार्ग भारतीय दर्शन के सूत्र 'सम्पूर्ण धरती एक परिवार' पर आधारित मानवीय बंधुत्व भाव से ही निकलेगा।

अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के आयोजन थीम आधारित होते हैं ताकि सम्बंधित विषय पर साझी समझ बनाई जा सके। वर्ष 2026 कि थीम 'विभाजन की जगह संवाद' वास्तव में मौन से मुखर होने की पैरवी करती है। किंतु यह मुखरता वाचालता एवं कट्टरता के लिए नहीं है अपितु सामाजिक सहिष्णुता की वृद्धि, सद्भाव के प्रसार एवं सतत संवाद के रास्ते खोलेगी। संवाद से ही अहंकार की परिधि पर खड़ी दीवार दरकती है और नये विचारों की ताजी हवा के लिए एक खिड़की खुलती है। दीवार पर खुली एक खिड़की आत्मीयता, मधुरता एवं करुणा के कोमल झोंकों के आवागमन हेतु रास्ता देती है और फिर ऐसी ही तमाम खिड़कियां दीवारों पर खुलने लगती हैं। विभाजन की जगह संवाद थीम अंतर्गत वैश्विक आयोजन कर स्वस्थ सुंदर सुवासित दुनिया रचने-गुनने की ओर हम सभी बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है।

भारतीय पत्रकार संघ का 555वां सम्मेलन खरगोन में, देशभर के पत्रकार शामिल हुए

खरगोन। पत्रकारिता के सम्मान, जनहित के मूल्यों और संगठित एकता के संकल्प के साथ भारतीय पत्रकार संघ (एआईजे) का राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान एवं कल्याण महोत्सव-2026 खरगोन की अभ्युदय यूनिवर्सिटी में हुआ। इसमें मध्यप्रदेश समेत देशभर के एक हजार से अधिक पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान कई चिकित्सा संस्थानों में पत्रकारों को रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी एमओयू की भी घोषणा की।

यह आयोजन पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी, राष्ट्र निर्माण का आधार और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त माध्यम मानने वाली विचारधारा का जीवंत प्रमाण बना। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों ने मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर पत्रकारिता को ज्ञान, विवेक और सत्य के मार्ग पर अग्रसर रखने का सामूहिक संकल्प लिया। अतिथियों के स्वागत के बाद 'एआईजे' के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि संगठन पिछले 12 साल से पत्रकार हितों के लिए समर्पित भाव से निरंतर कार्य कर रहा है। यह आयोजन एआईजे का 555वां वृहद आयोजन है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। उन्होंने बताया कि संगठन देश के 22 राज्यों में सक्रिय रूप से पत्रकारों के हित में कार्य कर रहा है।

पत्रकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए 27 से अधिक उच्च चिकित्सा संस्थानों एवं अस्पतालों के साथ एमओयू किए गए हैं।

वरिष्ठ पत्रकारों का मार्गदर्शन– 'सुबह सवेरे' के संपादक हेमंत पाल ने भी पत्रकारिता के सुव्यवस्थित विकास में एआईजे की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देशभर में संगठन का सक्रिय नेटवर्क होने का लाभ सदस्य पत्रकारों को हमेशा मिलता है। यही विश्वास इस पत्रकार संगठन को मजबूत बनाता है। वरिष्ठ पत्रकार तेज कुमार सेन ने भी अपने परिचित अंदाज़ में पत्रकारों से लेखन के साथ संगठित एकता की आवश्यकता पर बल दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पुष्पेंद्र वैध ने भी पत्रकारों को संबोधित किया।

अतिथियों का संबोधन– उद्घाटनकर्ता अतिथि और खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार खरगोन ने कहा कि पत्रकारों का यह ऐतिहासिक जमावड़ा खरगोन के इतिहास में अविस्मरणीय है। इसके अलावा मनावर के विधायक हीरालाल अलावा विधायक केदार डावर ने भी कार्यक्रम संबोधित किया। इस अवसर पर संकुश हॉस्पिटल रतलाम, रक्षा हॉस्पिटल खरगोन, एसएमएस हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉ मृदंग भावसार अहमदाबाद, पारुल यूनिवर्सिटी गोवा, मिलेनियम इन्फ्रा इंदौर सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पत्रकार हित में उल्लेखनीय घोषणाएं की। इन घोषणाओं में चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सहयोग एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल रहीं। कार्यक्रम के पावन सानिध्य दाता त्रिकालदर्शी रामलला सरकार (अयोध्या) ने विशाल संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा पत्रकार अपने समय का दान राष्ट्र के लिए करते हैं। यह कार्य राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। साधना न्यूज चैनल की तरफ से भी एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान, कल्याण महोत्सव में पत्रकारों के स्वास्थ्य पर एमओयू

'एआईजे' की सक्रियता को सराहा

कार्यक्रम संरक्षक और नवभारत के समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में 'एआईजे' के पत्रकार हितों के लिए किए जा रहे कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि एआईजे आज देश का सबसे बड़ा पत्रकार हितैषी संगठन बन चुका है। यह संगठन केवल बातें नहीं करता, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करता है। उन्होंने एआईजे के संस्थापक अध्यक्ष विक्रम सेन की कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और टीम भावना की विशेष प्रशंसा की। मुख्य अतिथि एवं डिजियाना न्यूज चैनल के एडिटर-इन-चीफ प्रतीक श्रीवास्तव ने पत्रकारों की कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि आज पत्रकार अनेक बंदिशों, दबावों और चुनौतियों के बीच काम कर रहे हैं। इसके बावजूद पत्रकारों का राष्ट्रीय प्रेम और कर्तव्य बोध प्रशंसनीय है। उन्होंने एआईजे के निरंतर प्रयासों को दमदार, जानदार और सार्थक बताते हुए मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

वीबी जी रामजी योजना, केन्द्र, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं

सुबह सवेरे सोहागपुर। सोहागपुर विधायक विजयपालसिंह के निवास पर वीबीजीरामजी योजना को लेकर भाजपा मंडल की कार्यशाला किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राजपूत एवं जिला उपाध्यक्ष श्री मुकेश सराठे के आतिथ्य में संपन्न हुई।दोनों अतिथियों ने ने वीबीजीरामजी योजना पर सारगर्भित उद्बोधन देते कहा कि उक्त योजना संगठन के पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर सशक्त करने, के लिए कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वो

आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने का कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। इसके साथ आगामी समय में होने वाले पार्टी कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों, बूथ विस्तार एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। आपने अंत में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक अनुशासन, एकजुटता एवं समन्वय के साथ कार्य करने का संदेश दिया।इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर थे वीबीजीरामजी योजना कार्यशाला में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना तथा आगामी कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियानों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की बात कही।।

कार्यशाला में भाजपा मंडल अध्यक्ष ,नगर पंचायत अध्यक्ष लता यशवंत पटेल–जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल पार्षद आशीष विश्वकर्मा, आकाश रघुवंशी, भगवान सिंह पटेल, पूर्व पार्षद भागश्री मनोज गोलानी, संध्या नागवंशी, सुधा श्रीवास सहित शोभापुर भाजपा मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अनुकरणीय पहल

शाला में फीस जमा न करने वाले बच्चों की फीस जमा की

सोहागपुर। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में सेवानिवृत्त एसडीओ सिंचाई विभाग महेश कुमार सोनी ने जो असमर्थ बच्चे जो फीस जमा नहीं कर पा रहे थे।स्कूल में श्री सोनी ने एक मसीहा के रूप में आकर मदद की। आपने गुरु नानक पब्लिक स्कूल मे करीबन 10 बच्चों की फीस जमा करके अनुकरणीय उदाहरण करके अनोखी पहल प्रारंभ की। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ज्ञानी सुरजीत सिंह ने उनका आभार व्यक्त किया है।इस अवसर पर पार्षद जमील खान, स्कूल स्टाफ, अभिभावकगण उपस्थित थे । श्री सोनी ने समाज में बच्चों के हित के लिए अपना एक हिस्सा उनकी पढ़ाई में देने का उनकी मुहिम चलाई है।

अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के चतुर्थ दिवस में चार मैच हुए, सोहागपुर ने सोनभद्र उत्तर प्रदेश टीम को हराया

सुबह सवेरे सोहागपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर प्रताप भानु सिंह चौहान की स्मृति में आयोजित 61 वें साल की अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2026 के चतुर्थ दिवस जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में चार प्रतियोगिता संपन्न हुई। चार मेंच उज्जैन, भोपाल, सिवनी छपरा, मंडीदीप, इटारसी, रायपुर छत्तीसगढ़, सोहागपुर एवं सोनभद्र उत्तर प्रदेश के मध्य खेले गए। आज का पहला मुकाबला उज्जैन एवं भोपाल की टीम के

बीच हुआ। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते उज्जैन ने भोपाल को 3-2 से पराजित किया। दूसरा मुकाबला सिवनी छपारा एवं मंडीदीप के बीच खेला गया। दोनों टीमों अत्यंत रोमांचिक प्रर्दशन किया।। अतः मुकाबले में मंडीदीप ने सिवनी छपारा को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। तीसरा मैच में इटारसी एवं रायपुर (छत्तीसगढ़) के बीच हुआ। इटारसी ने कलात्मक हांकी खेलते खेलते संघर्ष के उपरांत इटारसी टीम ने रायपुर छत्तीसगढ़ टीम को 2 गोलों से पराजित किया। रायपुर छत्तीसगढ़ की टीम कोई गोल नहीं बना सकी। चतुर्थ मुकाबला सोहागपुर बनाम उत्तर प्रदेश (सोनभद्र) के बीच खेला जा रहा है । इस ख़बर लिखे जाने तक दूसरे हाफ में उत्तर प्रदेश सोनभद्र की टीम 1-1 गोल से बराबरी पर चल रही थी। अंत में सोहागपुर टीम ने दो और गोल करके 3 के मुकाबले 1गोल से विजय हासिल की। दो गोलों से सोहागपुर की जीत दर्ज होने पर सोहागपुर के खेल प्रेमियों करतल ध्वनि से स्वागत किया।इस गरिमामय अखिल भारतीय हाकी प्रतियोगिता में नगर की प्रथम नागरिक सहित कई जानी-मानी हस्तियां के अलावा खेल समिति के पदाधिकारी, राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। इसके पूर्व अतिथियों ने विभिन्न हाकी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

प्रमंडल जोड़ से कामथ चौराहा तक बनेगा फोरलेन मार्ग, शासन को भेजा गया प्रस्ताव

मुलताई को जाम और दुर्घटनाओं से मिलेगी राहत

बैतूल/मुलताई। मुलताई नगर के मध्य से गुजरने वाले प्रमुख मार्ग पर लगने वाले बार-बार के जाम और बढ़ती दुर्घटनाओं से आगामी समय में नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रमंडल जोड़ से कामथ चौराहा तक लगभग 5.8 किलोमीटर लंबाई के मुख्य मार्ग को टू-लेन से फोरलेन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव को शीघ्र ही तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। मंजूरी मिलते ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यह मार्ग नगर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। मार्ग के दोनों ओर दुकानों की भरमार होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन अक्सर सडक़ किनारे खड़े रहते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति, दुर्घटनाएं और विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यातायात सुधार के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई प्रयास किए गए। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में समस्या जस की तस बनी रही। यही कारण है कि नगरवासी लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग करते आ रहे हैं।

राजनीति और उम्मीदों के बीच अटका रहा चौड़ीकरण– जब-जब मार्ग चौड़ीकरण की बात सामने आती है, नगरवासियों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो जाती है। पूर्व में भी कई बार इस मार्ग के लिए डीपीआर तैयार की गई, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अब एक बार फिर प्रस्ताव भेजे जाने से लोगों में उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि यह मार्ग बनते है तो आवागमन सुगम हो जायेगा। बारिश के दिनों में उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल विभाग द्वारा मार्गो के प्रस्ताव भेजने के बाद लोगों में सडक़ निर्माण की उम्मीद जागी है।

पूर्व में 22 करोड़ की डीपीआर हुई थी निरस्त– उल्लेखनीय है कि बीते एक दशक में इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कई बार डीपीआर बनाई गई। सकरी पुलिया के कारण हुई दुर्घटना में मौत के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर लगभग 22 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम/निर्माण समिति के मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण निरस्त कर दिया गया था। अब एक बार फिर नए सिरे से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार इसे शासन की स्वीकृति मिल पाती है या नहीं।

लोक निर्माण विभाग ने तीन प्रमुख मार्गों के भेजे प्रस्ताव

(1) लोक निर्माण विभाग द्वारा इस बार क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण मार्गों के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे गए हैं: प्रमंडल जोड़ से कामथ चौराहा (5.8 किमी) टू-लेन से फोरलेन में उन्नयन का प्रस्ताव।

(2) प्रमंडल जोड़ से सर्रा-हेटी होते हुए अंबाड़ा नरेरा मार्ग (30 किमी) सिंगल लेन को डबल लेन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव।इससे मुलताई से आमला एवं आमला से सारणी तक आवागमन और अधिक सुगम होगा।

(3) चिखली कला-रीधोरा होते हुए नागदेव मंदिर मार्ग -आमला ब्लॉक के प्रमुख तीर्थ नागदेव मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

इनका कहना है

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमंडल जोड़ से कामथ तक 5.8 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण एवं चिखली से नागदेव मंदिर तथा प्रमंडल जोड़ से अंबाड़ा मार्गों के टू-लेन निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजे गए हैं।

– डीआर कलमकर, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, मुलताई

धार जिले की टी-20 सीनियर क्रिकेट टीम घोषित

धार। इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला क्रिकेट स्पर्धा जो अलीराजपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 5 फरवरी से आयोजित की जाएगी।इस हेतु धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 1फरवरी को चयन ट्रायल्स न्यू डी.आर.पी. लाईन क्रिकेट मैदान पर हुआ।

सीनियर क्रिकेट टीम हेतु चयन प्रमोदशर्मा, महेंद्र सूर्वे अंबालाल पाटीदार ,निखिल ग्वाल ने जिला क्रिकेट कोच आलोक दुबे के मार्गदर्शन में चयन किया गया। स्पर्धा में जिले की समस्त तहसीलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया चयनित टीम इस प्रकार है! स्वराज तढ़वाल (कप्तान) (धार), प्रभात शर्मा (उपकप्तान) (धार), निलेश पटेल (मनावर), लक्षित बघेल (केसुर), सुदीप वर्मा (सरदारपुर), प्रवीण राठोड़ (धार), आर्यन चंदेल (धार), चेतन सिंह (धार), दीपक कुशवाह, आदित्य सक्सेना (धार), प्रांजल बघेल (धार), भव्य चोयल, गौरव वर्फा (रिंगनोद), (धामनोद), योगेश डाबर (धार),परम मकवाना। इंदौर दौरे हेतु टीम के कोच आलोक दुबे एवं मैनेजर यश चौहान रहेंगे चयनित टीम को एसोसिएशन के चेयरमैन करन सिंह पवार, अध्यक्ष प्रदीप जोशी, सचिव राजेन्द्र सिंह चौहान,उपाध्यक्ष धीरेंद्र दीघे, विनोद मित्तल, डॉ अजेश माइकल, अमित जैन, प्रमोद शर्मा, युनुस खान धरमपुरी आदि ने बधाई प्रेषित की। यह जानकारी एसोसिएशन के प्रवक्ता कुशल शर्मा ने दी।

संयुक्त राष्ट्र में गूंजा 'विकसित भारत' का संकल्प- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने रखा भारत का दृष्टिकोण

धार। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री एवं धार-महू से सांसद सावित्री ठाकुर ने सामाजिक न्याय, समावेशन एवं सतत विकास से जुड़े वैश्विक विषयों पर भारत का सशक्त पक्ष अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा।

भारत का विकास दृष्टिकोण 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना पर आधारित है– अपने संबोधन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री एवं धार-महू से सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि भारत का विकास दृष्टिकोण 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना पर आधारित है, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिलाओं, बच्चों, वंचित वर्गों, दिव्यांगजनों और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतिगत पहलों और नवाचारों को साझा किया।

पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है

श्रीमती ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' का संकल्प केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, लैंगिक समानता और मानवीय गरिमा के साथ प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भारतीय दर्शन को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अपने समावेशी विकास के अनुभवों को विश्व समुदाय के साथ साझा कर वैश्विक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत मानता है कि सतत और समावेशी विकास ही विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार है।

अंत में उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सामाजिक विकास के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा और मानव कल्याण को केंद्र में रखकर वैश्विक साझेदारी को नई दिशा देगा।

समबुद्ध सागर जी मुनिराज व सुविशुद्ध सागर जी मुनिराज का धार नगर में मंगल प्रवेश

धार। दिगंबर जैन समाज धार में आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य श्री समबुद्ध सागर जी मुनिराज एवं मुनि श्री सुविशुद्ध सागर जी मुनिराज का मंगल प्रवेश हुआ। मुनिराजद्वय बड़ौदा से इंदौर की ओर विहार कर रहे हैं जो अल्प प्रवास पर धार पधारे है। इस पावन अवसर पर मुनि संघ की आगवानी मानतुंग गिरी तीर्थ क्षेत्र पर अध्यक्ष नरेश गंगवाल, कोषाध्यक्ष किशोर

जैन, समाज अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल ने की। रात्रि विश्राम पश्चात पूज्य गुरुदेव का धार नगर में मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य गुरुदेव ने महती धर्म सभा में अपने मंगल प्रवचन कर संपूर्ण समाज को आशीर्वाद प्रदान किया इस अवसर बड़ी संख्या मे समाज जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव संजय छाबड़ा ने किया। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने दी।

सीमांकन के प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण: कलेक्टर

बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान कलेक्टर ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शाहपुर के ग्राम मंडई निवासी अंतराम यादव ने अपनी भूमि का सीमांकन नहीं होने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम शाहपुर से प्रकरण की जानकारी ली और आवेदक की भूमि का जल्द सीमांकन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में सभी एसडीएम और तहसीलदार को सख्त हिदायत दी कि सीमांकन के प्रकरण लंबित न रहें। सीमांकन के प्रकरणों

का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

एसडीएम और तहसीलदार को रास्ता खुलवाने के दिए निर्देश– जनसुनवाई में आमला के ग्राम सासाबढ़ निवासी मेघा बाई ने आवेदन के माध्यम से अपनी जमीन पर रास्ते विवाद के चलते हो रही परेशानी कलेक्टर को बताई, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने तत्काल रास्ता खुलवाने के निर्देश एसडीएम और तहसीलदार आमला को दिए। शाहपुर तहसील के ग्राम भौंरा निवासी बारातीलाल ने आवेदन के माध्यम से जमीन पर कब्जा होने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मुलताई के पटेल वार्ड निवासी रिंकी पवार ने आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्री अनुसार रिकॉर्ड अभिलेख दुरुस्त किए जाने की मांग की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित एसडीओ रेवेन्यू मुलताई को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

मुआवजा राशि दिलवाने की मांग– जनसुनवाई में बैतूल निवासी राजेश पवार ने नामांतरण कर भूमि प्रबंधन से हटाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम चिखली खुर्द निवासी अनिल धोटे ने मुआवजा राशि दिलवाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने एसडीओ मुलताई को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम महतपुर निवासी सुखदेव ने रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने मुलताई एसडीओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।ग्राम जामन्या निवासी चंपालाल ने गलत दस्तावेजों के माध्यम से हो रहे सीमांकन को रोकने के लिए आवेदन दिया।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर ने विधानसभा बजट सत्र के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने 16 फरवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक चलने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा के प्रश्न जैसे ही प्राप्त होते हैं तत्काल उसके उत्तर तैयार कर भेजने की व्यवस्था की जाये। विधानसभा के उत्तर समयावधि में सही एव पूरक जानकारी सहित भेजने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा प्रभारी अधिकारी का होगा। जिला कार्यालय के राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर परीक्षण कर समयावधि में भेजने हेतु अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर न जाएं। बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए है कि जिला कार्यालय एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाये तथा नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए, जो विधानसभा से संबंधित पत्राचार के लिए उत्तरदायी हो। इसके साथ ही विधानसभा बजट सत्र के दौरान सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

लक्ष्य प्राप्त होते ही प्राथमिकता से भेजा जाएगा प्रकरण, हितग्राही को दी गई योजना की पूरी जानकारी

विदिशा (निप्र)। जिला प्रशासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी क्रम में ग्राम फतेहपुर निवासी हितग्राही श्री ओमकार अहिरवार को संबंधित योजना के बारे में कार्यालय में बुलाकर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एससी/एसटी वर्ग से संबंधित प्रकरणों के लिए निर्धारित लक्ष्य (टारगेट) प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण आवेदन की स्वीकृति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी है। हालांकि, हितग्राही का प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रूप से संधारित कर लिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही आगामी समय में संबंधित श्रेणी के लिए लक्ष्य प्राप्त होंगे, श्री ओमकार अहिरवार का आवेदन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेजी कार्यवाही पहले से पूर्ण कर ली जा रही है, ताकि लक्ष्य प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया सीहोर जिला जेल का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने सीहोर जिला जेल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेल में विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सजायाफ्ता बंदियों के अभिलेखों का अवलोकन किया और इस संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बंदियों की सजा अवधि की भी समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सजा पूर्ण होने के बाद कोई भी बंदी जेल में बंद न रहे। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और यथोचित निराकरण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जेल की पाकशाला, डिस्पेंसरी, महिला एवं अन्य बैरकों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, जेल अधीक्षक सुश्री प्रतिभा पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राशन वितरण में अनियमितताएं करने और ईकेवाइसी कार्य नहीं करने वाली उचित मूल्य दुकानों पर की गई कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण कम होने, प्रतीक्षारत परिवारों की ईकेवाइसी नहीं करने एवं नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलने पर खाद्य विभाग द्वारा आष्टा एवं बुधनी अनुभाग की अनेक उचित मूल्य दुकानों पर कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि आष्टा अनुभाग के सिद्दीकगंज, कोटियानाला, सेमलीबारी, कांकरियाखेरी स्थित राशन दुकानों पर प्रकरण निर्मित कर 3000 रूपये की चालानी कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार कोटियानाला एवं कन्नोदमिर्जा की राशन दुकान विक्रेताओं को जनवरी में वितरण प्रतिशत कम होने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। इसी क्रम में बुधनी अनुभाग की रतनपुर, कुसुमखेड़ा, नानभेंट, जोनतला, बकतरा, कोसमी एवं रेहटी के राशन दुकान विक्रेताओं के विरूद्ध वितरण कार्य में लापरवाही करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत् प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

सुल्तानपुर में 10 फरवरी को आयोजित होगा जिला स्तरीय युवा संगम मेला

रायसेन (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2026 को नगर परिषद प्रांगण सुल्तानपुर में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक आयोजित किया गया है। इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

'रोगी से न करें भेदभाव, कुष्ठ रोग के बारे में हो जागरूक'

विश्व कुष्ठरोग दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ''विश्व कुष्ठरोग दिवस'' के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, विकास नगर, हरदा में कुष्ठ रोग के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित जनों को कुष्ठ रोग की बीमारी तथा इस रोग के लक्षण, कारण एवं बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। श्री राठौर ने बताया कि ''विश्व कुष्ठरोग दिवस'' हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, इससे जुड़े मिथ्यों को दूर करना तथा प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना है। साथ ही यह भी बताया गया कि कुष्ठ रोग की बीमारी छूआछुत से नहीं फैलती अपितु यह एक ''माइकोबैक्टिरियम लैपी'' नामक एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक दीर्घकालीक संक्रामक रोग है, जो मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, यह रोग मुख्य रूप से हाथों, पैरों और चेहरे को प्रभावित करता है। इस बीमारी का पूर्ण ईलाज ''मल्टी ड्रग थैरेपी'' के माध्यम से संभव है, जो सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मूफ्त में उपलब्ध है। साथ ही कुष्ठ रोग से जुड़े विविध तथ्यों से लोगों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने विश्व कुष्ठ रोग दिवस को मनाये जाने के महत्व के बारे में बताया तथा इससे प्रभावित रोगियों के लिए शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि रोगी किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। साथ सही नालसा/सालसा की विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं नालसा लैंगिक हमलों, अन्य अपराधों की पीड़िताओं अथवा सर्वाईवर्स के लिए प्रतिकर योजना 2018, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा योजना, 2015, नालसा-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के बारे में जानकारी दी तथा बताया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने इस दौरान निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। शिविर में डॉ. पूजा अहिरवार, महिलाएं, बच्चे एवं पैरालीगल वॉलेंटियर सुनिता साहू उपस्थित रहे।

राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ 27वां देहदान, स्व. राजाराम पवार ने मानवता को किया अंतिम समर्पण

विदिशा (निप्र)। पीड़ित मानवता की सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए आज्ञाराम कॉलोनी, गांधी नगर विदिशा निवासी स्व. श्री राजाराम पवार का देहदान राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। श्री विकास पचैरी फाउंडेशन द्वारा संचालित देहदान, नेत्रदान एवं रक्तदान जागरूकता मिशन के अंतर्गत रविवार को अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, विदिशा में उनके पार्थिव शरीर की देहदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस देहदान के साथ मेडिकल कॉलेज में फाउंडेशन के सहयोग से दान किए गए पार्थिव शरीरों की कुल संख्या 27 हो गई है।

स्व. राजाराम पवार एवं उनकी पत्नी श्रीमती शोभा पवार ने 16 जुलाई 2019 को फाउंडेशन के अभियान से प्रेरित होकर मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया था। उन्होंने विधिवत वसीयत में उल्लेख किया था कि मृत्यु के पश्चात उनका पार्थिव शरीर किसी भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, ताकि उनका शरीर चिकित्सा शिक्षा और मानव सेवा के कार्य आ सके। बीते दिनों उनके निधन के उपरांत परिजनों ने समाजसेवी विकास पचैरी के सहयोग से रविवार को उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। देहदान से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा स्व. पवार के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अर्पित किया गया तथा पुलिस बल ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में परिजनों, मेडिकल स्टाफ और अन्य उपस्थितजनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजसेवी विकास पचैरी ने बताया कि देहदान संकल्प प्रक्रिया पूर्णतः निरूशुल्क है। इच्छुक व्यक्ति आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शेरपुरा, विदिशा स्थित सेवा घर पहुंचकर संकल्प प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देहदान से चिकित्सा शिक्षा को मजबूती मिलती है और यह मानवता के लिए सर्वोच्च सेवा का कार्य है।

आशा कार्यकर्ता ईमानदारी से निभाएं दायित्व, स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम कड़ी हैं : एसडीएम मनीष जैन

विदिशा (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुरवाई में रविवार को आशा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना तथा फील्ड स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना रहा। बैठक में एसडीएम मनीष जैन ने आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनका कार्य सीधे तौर पर मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने से जुड़ा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे ड्यू लिस्ट के अनुसार घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों की जानकारी अद्यतन रखें तथा संभावित गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान सुनिश्चित करें। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह मां और नवजात दोनों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉ. प्रमोद दीवान ने अपने संबोधन में आशा कार्यकर्ताओं को अपने दायित्वों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्वे ड्यू लिस्ट के आधार पर कार्य करने से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श तथा संस्थागत प्रसव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) ने विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत अहम है। उन्होंने समयबद्ध रिपोर्टिंग, सही डेटा संकलन और फील्ड स्तर पर सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य में आने वाली व्यावहारिक समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि फील्ड में बेहतर कार्य के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

गौवंश को हर समय पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर जोर : कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज जिले की सभी शासकीय गौशालाओं के संचालन एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा एन आई सी व्हीसी कक्ष में करते हुए भविष्य के लिए सुदृढ़ चारा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक गौशाला में दीर्घकालिक चारा प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में गौवंश को चारे की कमी का सामना न करना पड़े।

अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सीएमएचओ व डीटीओ ने दिए दिशा-निर्देश

विदिशा (निप्र)। आज लटेरी स्थित अंबेडकर भवन में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) तथा जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी और मैदानी अमला उपस्थित रहा। बैठक का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करना तथा फील्ड स्तर पर आ रही चुनौतियों की समीक्षा करना रहा। सीएमएचओ ने सभी कार्यक्रम प्रभारियों से योजनावार प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, गैर संचारी रोगों की जांच, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम सहित अन्य प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) ने विशेष रूप से टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच और नियमित उपचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए तथा उपचाराधीन मरीजों की सतत मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में डेटा रिपोर्टिंग, पोर्टल पर समयबद्ध जानकारी अपडेट करने, फील्ड विजिट बढ़ाने और लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब मैदानी स्तर पर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अंत में उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाएं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारी कर्मचारियों को दिये निर्देश

हरदा (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ ने शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विस्तृत एवं बिंदुवार समीक्षा की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जोसेफ ने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर सौंपे गए लक्ष्यों के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विलंब अथवा उदासीनता को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी समीक्षा बैठक में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। इसके उपरांत भी सुधार नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

समीक्षा बैठक में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग हरदा, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण, सहायक यंत्री, उप यंत्री, बीडीओ, पीसीओ, ब्लॉक समन्वयक सहित जिला पंचायत कार्यालय के सभी शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं जनहितैशी क्रियान्वयन के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को योजनाओं का पूर्ण लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

गेंदे की खेती से कृषक कलीराम को 2 लाख का हुआ मुनाफा

बैतूल (निप्र)। ग्राम सुरगांव निवासी प्रगतिशील कृषक श्री कलीराम बनकर के लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं, अब जिंदगी की सबसे मजबूत कमाई बन चुकी है। परंपरागत खेती से आगे बढ़कर उन्होंने गेंदे की खेती को अपनाया और आज वही खेती उन्हें कम समय में बेहतर और स्थायी मुनाफा दिला रही है। कृषक कलीराम ने बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से लगातार गेंदे की खेती कर रहे हैं। हर बार वे करीब 25 हजार रुपये की लागत से फसल तैयार करते हैं और मात्र तीन महीनों के भीतर लगभग 2 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी अर्जित कर लेते हैं। उनका कहना है कि गेंदे की खेती ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और परिवार की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गेंदे की खेती की उन्नत तकनीक में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का समय-समय पर मार्गदर्शन उन्हें मिलता है, इसके साथ ही विभाग से उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई, जिस पर शासन से अनुदान का लाभ मिला और पानी की बचत के साथ लागत भी कम हुई।कलीराम बनकर ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि वे परंपरागत फसलों तक सीमित न रहें और फूलों की खेती जैसे लाभकारी विकल्प अपनाएं। उनका कहना है कि कम जमीन और कम लागत में भी किसान सम्मानजनक आमदनी कमा सकते हैं। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक

सीहोर (निप्र)। हर साल 02 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमें उन प्राकृतिक जल क्षेत्रों की याद दिलाता है, जो जीवन, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह दिवस आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पृष्ठभूमि 02 फरवरी 1971 से जुड़ी है, जब ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हुआ। तभी से इस दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र हैं, जहाँ पानी स्थायी या अस्थायी रूप से

मौजूद रहता है। इनमें झीलें, तालाब, नदियाँ, दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव वन और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आर्द्रभूमियों का महत्व और भी अधिक है। मध्यप्रदेश की बड़ी आबादी पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका के लिए आर्द्रभूमियों पर निर्भर है। आर्द्रभूमियाँ भूजल स्तर बनाए रखने, बाढ़ नियंत्रण और सूखे के प्रभाव को कम करने में सहायक होती हैं। साथ ही ये प्रवासी पक्षियों और दुर्लभ वन्य प्रजातियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल भी हैं। वर्तमान में भारत में अनेक आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, जो संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि, तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन आर्द्रभूमियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। कई पारंपरिक तालाब, झीलें और जल क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं, जिससे जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या गहराती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। आर्द्रभूमियों में कचरा फेंकने पर रोक, अवैध अतिक्रमण हटाना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ना और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इनके महत्व से अवगत कराना समय की आवश्यकता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि आज हमने आर्द्रभूमियों को नहीं बचाया, तो भविष्य में जल, पर्यावरण और जैव विविधता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति के इस अनमोल उपहार के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास ही एक सुरक्षित और सतत भविष्य की कुंजी है।

आयुष्मान भारत योजना की इन्सेंटिव वितरण प्रणाली को बनायें पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध : शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों एवं सहायक चिकित्सकीय स्टॉफ को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली इन्सेंटिव व्यवस्था की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि इंसेंटिव वितरण प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि पात्र चिकित्सकों एवं स्टॉफ को समय पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने डेटा एंट्री प्रक्रिया को सरलीकृत एवं सुगम बनाने तथा समयबद्ध डेटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मैन पॉवर की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कुशल एवं दक्ष मैनपावर को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे उनका मनोबल बना रहे और वे पूर्ण ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय कर सकें। इससे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। बैठक में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराजु एस एवं आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. योगेश भरसट उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वैश्विक मंच पर सशक्त हुआ भारत : उप मुख्यमंत्री

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार समझौता भरोसेमंद और दूरदर्शी साझेदारी संबंधों का सशक्त प्रतिबिम्ब

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वासी और प्रभावशाली शक्ति बना है। आर्थिक सुधारों, वैश्विक सहयोग और सतत विकास के प्रति प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच गहरे, भरोसेमंद और दूरदर्शी साझेदारी संबंधों का सशक्त प्रतिबिंब है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति प्रदान करेगा तथा निवेश, नवाचार और औद्योगिक सहयोग के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहभागिता को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी। यह व्यापार समझौता भारत की विकास यात्रा को और तेज करेगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करेगा तथा दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि में सार्थक योगदान देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और भारत के समग्र विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नर्मदा की सेहत पर एनजीटी सख्त

मध्य प्रदेश की जीवनरेखा को लेकर बड़ी चेतावनी
एनवायरमेंट सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट

भोपाल (नप्र)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भोपाल बेंच ने पर्यावरण के प्रधान सचिव को नर्मदा नदी को साफ रखने के लिए दिए गए निर्देशों पर एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट विभिन्न एजेंसियों, विभागों, जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों से संकलित की जाएगी। एनजीटी ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

नर्मदा को जीवन रेखा बनाए रखने के लिए निर्देश

एनजीटी ने नर्मदा नदी के बाढ़ क्षेत्र को चिह्नित करने, उस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने, नदी में बिना उपचारित सीवेज और ठोस कचरा बहाने पर रोक लगाने, अवैध रेत खनन बंद करने और पूरे साल नदी के प्रवाह को स्थिर रखने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बनाए रखने के लिए हैं।

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

यह अनुपालन रिपोर्ट 1 सितंबर, 2025 को एनजीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तैयार की जानी है। यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता कीर्ति कुमार सदाशिव भट्ट की याचिका पर आधारित है। रिपोर्ट को एनजीटी के रजिस्ट्रार को सौंपा जाएगा, जो इसे ट्रिब्यूनल के सामने पेश करेंगे। इसके बाद, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निष्पादन याचिका पर सुनवाई

एनजीटी ने यह टिप्पणी जबलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता पी.जी. नज्पांडे द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका पर सुनवाई करते हुए की। एनजीटी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। इसी के लिए एनजीटी ने अब मुख्य सचिव (पर्यावरण) को इस मामले में निर्देशित किया है।

तार में गर्दन फंसने से कटी गर्दन, साथ में थे 3 भाई

सतना में ट्रैक्टर से मिक्सर मशीन खींचने बांधे थे तार; बहन के घर जा रहे थे

सतना (नप्र)। सतना में कोठी रोड पर बाइक सवार युवक की गर्दन तार में फंसने से कट गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में उसके दो रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सोमवार रात करीब 11 बजे गढ़िया टोला कब्रिस्तान के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार का कर्मचारी ट्रैक्टर से एक भारी-भरकम मिक्सर मशीन को तार बांधकर सड़क के दूसरी ओर ले जा रहा था। इसी दौरान सिविल लाइन की तरफ से आ रहे बाइक सवार तीन युवक तार में उलझ गए और सड़क पर गिर पड़े। बाइक चला रहे रामजस (45) पुत्र रामकृपाल चौधरी, निवासी कंचनपुर-अमरपाटन की गर्दन तार में फंसने से कट गई। वहीं, अरविंद (38) पुत्र रामसिपाही चौधरी निवासी उदयसागर और रामप्रसाद (40) पुत्र हरिदीन चौधरी निवासी रामपुर चौरासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तीनों मौसेरी बहन की ससुराल जा रहे थे- पुलिस के मुताबिक, मृतक और दोनों घायल मौसेरे भाई हैं। वे अपनी एक मौसेरी बहन की ससुराल बगहा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रामजस बाइक से सतना पहुंचा था। यहां से वो सिविल लाइन से अरविंद और रामप्रसाद के साथ बगहा के लिए निकला था। पुलिस ने शव को मॉर्चुरी में रखवा दिया है। ट्रैक्टर-मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की।

आम बजट लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था का पर्याय है : रघु ठाकुर

भोपाल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय बजट मुनीम साहब की खाता-बही है। जिसमें ना कोई दिशा है - ना कोई जनहितकारी बड़े उपाय हैं - ना कोई उम्मीद है। बस केवल आवक-जावक दर्ज हैं। कहने को सबका साथ और सबका विकास है। परंतु, वास्तव में कॉर्पोरेट का साथ और बाकी सबका विनाश है। देश की कुल आय में कॉर्पोरेट की टैक्स हिस्सेदारी कम है और आमजन की टैक्स हिस्सेदारी ज्यादा है। जबकि, होना यह चाहिए था कि कॉर्पोरेट का टैक्स बढ़ाकर आमजन को राहत दी जाती। कुल मिलाकर यह बजट यथास्थिति का बजट है। डेटा कंपनियों को आगामी 22 वर्ष के लिए टैक्स होलीडे यानि टैक्स की छूट दे दी गई है। देश को उम्मीद थी कि सरकार आयुष्मान की व्यवहारिक कमियों को देखकर या तो उसे संशोधित करती या फिर चिकित्सा का मूल अधिकार बनाकर आमजन को आवश्यक और पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराती। उच्च शिक्षा के नाम पर सरकार ने विदेश में यात्रा, पढ़ाई और पैसे भेजने पर जो 10 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत टैक्स था और 10 लाख से ऊपर 20 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे घटकर 2 प्रतिशत कर दिया है। निःसंदेह इससे विदेश में जाकर पढ़ने वालों को सुविधा होगी। परंतु, भारत की शिक्षा के लिए चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, कोई प्रावधान नहीं है और उन्हें खुले बाजार पर छोड़ दिया गया है। सरकारी स्कूल जो शिक्षकों के अभाव में बंद हो रहे हैं, उसके लिए भी, कोई उपाय नहीं किए हैं तथा शिक्षा के बजट का बड़ा हिस्सा निर्माणकार्यों तथा यूनिवर्सिटी टाउनशिप आदि पर खर्च होगा। कालेधन संचय करने वालों के प्रति सरकार मेहरबान है और विदेशों में अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए तक की संपत्ति की जानकारी नहीं देता तो उसे पहले जो जेल में जाने का प्रावधान था, वह, अब नहीं होगा। यह काले धन के मालिकों के लिए काला-धन छुपाने की खुली छूट होगी। सरकार ने देश को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय किया है। परंतु, इसके लिए देश के 500 शहरों में से 50 शहर चिन्हित किए हैं यानि गांव, कस्बा और छोटे शहरों को छोड़कर केवल महानगरों का ही विकास होगा।

रेप की कोशिश के बाद युवती की हत्या

- रायसेन में भाग रहे आरोपी को गांव वालों ने पकड़कर पीटा; अस्पताल में मौत

रायसेन (नप्र)। रायसेन के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भारतीपुर गांव में सोमवार दोपहर एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती अपने भाई के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की।

विरोध करने पर आरोपी ने युवती के जबड़े और गर्दन पर बके से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। मारपीट में घायल आरोपी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया।

भाई के लिए खाना लेकर निकली थी युवती- पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय युवती सोमवार दोपहर अपने भाई के लिए खेत पर खाना लेकर घर से निकली थी। रास्ते में गांव का ही प्रकाश सिंह भिलाड़ा उसे मिला, जिसने उसे रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की।

जबरदस्ती की कोशिश, विरोध पर हमला- युवती ने इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार बका से उसके जबड़े और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई।

हमले के बाद आरोपी लड़की को घसीटते हुए खेत के अंदर ले गया। मौके पर युवती के शरीर के निचले कपड़े नहीं थे, जिससे उसके साथ रेप की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच कर रही है।

आरोपी मौके से फरार, ग्रामीणों ने पकड़ लिया- वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपी की तलाश में निकल पड़े और कुछ ही दूरी पर कमरोरा क्षेत्र की घोघरा नदी के पास आरोपी घायल हालत में मिला।

ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को घायल हालत में अस्पताल भिजवाया गया।

इलाज के दौरान आरोपी की भी मौत- अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात आरोपी युवक प्रकाश सिंह भिलाड़ा ने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया कि मृतक युवती और आरोपी युवक के घर आमने-सामने स्थित हैं।

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने इस मामले में युवती के परिजन की ओर से हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी युवक की मौत के मामले में भी परिजन की शिकायत पर अलग से जांच की जा रही है।

6 लोग हिरासत में, पुलिस पूछताछ कर रही- पुलिस ने घटना से जुड़े मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनता देख पुलिस बल तैनात किया गया है।

दोनों के घर आमने-सामने, पहले से पहचान थी- बताया जा रहा है युवती कुछ साल पहले बाड़ी में रहकर पढ़ाई करती थी। इस दौरान युवक के संपर्क में आई थी। दोनों के घर भी आमने-सामने हैं।

प्रेमिका बोली-बच्चे हैं, शादी नहीं कर सकती

प्रेमी ने उसके बेटे का गला घोंटा, खदान में फेंकी लाश, दूसरे बच्चे को भी मारने वाला था

शहडोल (नप्र)। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रेमी ने प्रेमिका के बेटे को मार डाला। आरोपी ने गला घोंटकर शव को कोयला खदान में फेंक दिया। बच्चा आरोपी को मामा कहकर बुलाता था। इसी का फायदा उठाकर घुमाने ले गया और हत्या कर दी। मामला धनपुरी थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मोइशीन खान है, जो छत्तीसगढ़ में ड्राइवर का काम करता था। वहीं प्रेमिका अपने बच्चे और पति के साथ धनपुरी में रहकर मजदूरी करती है। आरोपी अपनी प्रेमिका से लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। वह नहीं मानी तो उसके बच्चे की हत्या कर दी।

पुलिस ने मर्डर को लेकर सोमवार रात खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी प्रेमिका के लिए उसके दूसरे बच्चे को भी मारने की साजिश रच चुका था, लेकिन उससे पहले पकड़ा गया।

यह थी पूरी वारदात- दरअसल, 27 जनवरी को 7 साल का ऋतिक कोल अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने बच्चे के बारे में आसपास और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद 27 जनवरी को बच्चे की मां ने धनपुरी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

ऋतिक कोल, मृतक

महिला ने बताया कि 26 जनवरी को आरोपी मोइशीन खान उसके घर पहुंचा था। इस दौरान वह कहने लगा कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मेरे साथ क्यों नहीं रहती। इस पर महिला ने साफ कह दिया कि वह अपने बच्चों और पति को छोड़कर उसके साथ नहीं जाएगी। प्रेमिका की इसी बात से गुस्साए प्रेमी मोइशी ने महिला को धमकी दी थी कि वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरे दिन से बेटा लापता है। परिजनों ने बच्चे के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। वहीं शिकायत के बाद धनपुरी पुलिस ने बच्चे की तलाश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। इसी बीच एक महिला ने बताया कि आरोपी मोइशीन खान को खदान में उतरते और चढ़ते देखा था। इस दौरान आरोपी ने भी उस महिला को देख लिया था।

महिला को देखकर खदान से भागा आरोपी- महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी फौरन खदान से डर के कारण भाग गया। वहीं महिला ने इस बात की जानकारी धनपुरी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस का शक और गहरा हुआ। पुलिस ने आरोपी मोइशीन खान को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी मोइशीन ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती बरतने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने यह भी बताया कि वह महिला से बेहद प्यार करता है। उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था।

बच्चे को बाइक में घुमाने के बहाने ले गया था आरोपी

आरोपी ने बताया कि 27 जनवरी को महिला के घर पहुंचा। मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर बाइक पर घुमाने का बहाना बनाया। बच्चा उसे मामा कहता था, इसलिए बिना किसी डर के उसके साथ चला गया। आरोपी बच्चे को बंद पड़ी कोयला खदान के पास ले गया। बच्चे का गला घोंटा, फिर शव को पानी से भरी खदान में फेंक दिया। आरोपी ने बताया कि अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए वह दूसरे बच्चे को भी मारने की साजिश रच चुका था, लेकिन पहले बच्चे की हत्या के बाद खदान से निकलते वक्त एक महिला ने देख लिया, जिसके वह घबरा गया था।

कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा- धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो ने बताया कि 30 जनवरी को खदान से बच्चे की लाश मिली है। आरोपी महिला से बार-बार शादी के लिए कह रहा था, लेकिन वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिससे आरोपी गुस्से में बच्चे की हत्या की।

धनपुरी थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

शिवपुरी में बिजली गिरी, किसान जिंदा जला

ग्वालियर-मंदसौर में ओले, भिंड समेत 8 जिलों में बारिश, दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें लेट

भोपाल (नप्र)। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में ओले, बिजली, बारिश और आंधी का दौर जारी है। बीती रात से मंगलवार सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में ओले-बारिश का दौर जारी रहा। शिवपुरी में झोपड़ी पर बिजली गिरने से किसान जिंदा जल गया।

ग्वालियर और मंदसौर जिले में ओले गिरे, जबकि भोपाल, भिंड, छतरपुर, राजगढ़, आगर-मालवा और गुना में बारिश हुई। इससे पहले सुबह रायसेन में ओस की बूंदें जम गईं। ग्वालियर में ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में मावठा गिरने का अलर्ट जारी किया है। भोपाल और सीहोर में 50 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज की गई। यानी, यहां पर 50 मीटर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।

दतिया, रायसेन, उज्जैन, मुरैना, देवास, धार, इंदौर, खजुराहो, रीवा, सतना, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, राजगढ़, रतलाम,

श्योपुर, शिवपुरी कोहरे के आगोश में रहे। इसके साथ ही मंडला, नौगांव, टीकमगढ़, मलाजखंड भी घने और मध्यम कोहरे का असर दिखा।

इस वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। इधर, रात के तापमान में गिरावट नहीं हुई है। सभी शहरों में पारा 10 डिग्री के पार ही रहा। हालांकि, बारिश का दौर थमने के बाद ठंड का एक दौर आ सकता है।

अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम-4 फरवरी- शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मध्यम कोहरा रहेगा।

5 फरवरी- राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा रहेगा।

6 फरवरी- गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा रहेगा।